MR. DEPUTY CHAIRMAN: Rule 214 A (5) read by Mr. Dave says:

> "If a member finds that he has voted by mistake by pressing the wrong button, he may be allowed to correct his mistake provided he brings it to the notice of the Chairman before the result of the division is announced."

On the day on which the votes were recorded several Members represented that they had made wrong voting and, therefore, their vote was recorded by voice. This could not be checked up with the photostat copy which came to the Office only the next day. And I find that ten persons have voted twice. What is now sought to be done is only to correct the records in consonance with the photostat copy, and nobody's vote is taken away either for "Ayes" or for "Noes". I find that there is no point of order and the ruling given is correct.

SHRI GANGA SHARAN SINHA: Sir, in protest against this ruling we walk out.

SHRI ROHIT M. DAVE: A wrong precedent is created.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, we do not accept that ruling. Therefore, we also walk out in protest.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You cannot protest.

(At this stage some hon. Members left the House.)

---

12 NOON

RESOLUTION *RE* SETTING UP OF A PERMANENT MINORITIES COMMISSION—*continued.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I find from the records that Mr. Bhupesh Gupta has moved his Resolution. So if any of the Members wants to speak on the Resolution, he can do so, after I place the Resolution before the House.

The question was proposed.

श्री पां० ना० राजभोज (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, राष्ट्रीय एकता और तादात्म्य की आज जितनी आवश्यकता है उतनी सिर्फ आजादी प्राप्त करने के पहले ही थी क्योंकि पंचवार्षिक आयोजना को सफल कर के हमारा उद्देश्य केवल आर्थिक तथा औद्योगिक प्रगति का पहिया ही मजबूत करना नहीं है, किन्तु चीन के आक्रमण को रोकने के लिये तथा पुर्तगाली सत्ता से मुकाबला करने के लिये सरकार के हाथ मजबूत कर के उसके पीछे एकता से खड़े रहने की आज आवश्यकता है और इस दृष्टि से मैं श्री भूपेश गुप्ता के इस प्रस्ताव की तरफ देखता हूं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य तो ठीक है किन्तु प्रश्न यह है कि माइनौरिटी कमीशन नियुक्त कर के वह प्रश्न हल होगा या नहीं ?

हमारे भारत में शुरू से ही ऐसी बात हुई है कि यहां अनेक प्रकार की माइनौरिटीज हैं। आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक कारणों से ऐसा हुआ है। और यह बात माननी ही पड़ेगी कि इसमें से ही भाषावाद, सम्प्रदायवाद, जमातवाद तथा जातीयवाद पैदा होते हैं और हुए हैं। इसलिए हमें यह देखना होगा कि क्या श्री भूपेश गुप्ता की जो सूचना है, क्या वह सूचना माइनौरिटीज के प्रश्न को हल कर सकती है या नहीं ? भाषायी माइनौरिटीज के लिए हमने संविधान के मुताबिक भाषायी अल्पसंख्यकों का संरक्षण करने के लिए एक कमिश्नर नियुक्त किया है और उसकी दो रिपोर्टें आ चुकी हैं। भाषायी मामले को लेकर आसाम में जो दंगे हुए वे अब खत्म हो रहे हैं। उससे जो दो भाषायी गुटों में बैर-भाव पैदा हुआ था वह मिट रहा है। मुख्य मंत्रियों की परिषद् में तथा नेशनल इन्टीग्रेशन कान्फरेन्स में इस प्रश्न पर विचार हो चुका है। उसके बारे में मुख्य मंत्रियों की परिषद् ने कहा है कि :

"The right of linguistic minorities to have instruction in their mother-tongue at the primary stage of education was reaffirmed. This has indeed received a constitutional recognition from Article 350A and the President is empowered to issue directions where necessary."

उपसभापति जी, हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर के और सरकार ने तीन भाषा का जो फार्मूला बनाया है उससे यह प्रश्न इतना जटिल नहीं रहेगा जितना माना जाता है ।

अब दूसरे प्रकार की माइनौरिटीज हैं, जो कि धार्मिक हैं और जिनका जिक्र श्री गुप्ता ने किया है । उसमें उन्होंने भारत में स्थित मुस्लिम जमात की बात कही है । मैं मानता हूं कि मुस्लिम जमात को कई ग्रीवैन्सेज हो सकते है । लेकिन यह मानना पड़ेगा कि सिर्फ मुस्लिम धर्मीय माइनौरिटीज ही नहीं हैं । यहां अन्य धर्म के लोग भी हैं, जैसे क्रिश्चियन, सिख और बुद्धिस्ट हैं । महाराष्ट्र में शैड्यूल्ड कास्ट जमात के अनेक लोग बुद्धिस्ट बने हैं और नव बौद्धों का एक गुट निर्माण हुआ है । क्या आप चाहते हैं कि उनका भी प्रश्न यह कमीशन बना कर सतत जिंदा रखा जाये ? महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण ने इन बुद्धिस्ट लोगों को बैकवर्ड कम्युनिटी के जरिये से सहूलियतें दी हैं । मैं यह बात इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि अन्य जगह ये सहूलियतें उपलब्ध नहीं की गई हैं । मैं उनको बधाई तो देता ही हूं किन्तु अर्ज करता हूं कि अन्य राज्यों में भी नव बौद्धो को भी वे सब सहूलियतें उपलब्ध की जायें जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को उपलब्ध हैं, नहीं तो इनका प्रश्न भी श्री भूपेश गुप्ता रिलीजस माइनौरिटीज के जरिये से सदन के सामने ले आयेंगे, और इस बात में भी ताज्जुब नहीं होगा कि एक दिन वे अकालियों का प्रश्न भी रिलीजस माइनौरिटीज के नाम पर इस सदन के सामने ले आयें ।

श्री भूपेश गुप्ता ने ककहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट में एक भी मुस्लिम जज नहीं है । मैं उन से पूछता हूं कि क्या मुस्लिम मंत्री, मुस्लिम एम्बेसेडर्स, मुस्लिम गवर्नर्स नहीं हैं ? यदि आप इस हिसाब से काम करेंगे तो देश के अन्य धर्मियों के लोग भी यही प्रश्न एजीटेशन करके उठायेंगे और कम्युनिस्टों को तो एजिटेशन पसंद ही है । इस से देश में कौमीवाद खत्म नहीं होगा लेकिन जिंदा रहेगा और बढ़ता जायेगा । एक अलग नेमी माइनौरिटी कमीशन स्थापित करने से मुस्लिम लीग, जनसंघ , हिन्दू महासभा जैसे जातीय संगठनों को प्रोत्साहन मिलेगा ।

उपसभापति महोदय, यह प्रस्ताव अभी चुनाव के नजदीक आने के वक्त लाया गया है । कम्युनिस्टों को केरल में मुस्लिम लीग से ओपनली एलायन्स करना नहीं है किन्तु पार्लियामेंट में उनके ग्रीवैन्सेज को बूस्ट अप करके उनका प्रेम प्राप्त करना है । इसी वास्ते, उपसभापति जी, मेरी यह प्रार्थना है कि श्री भूपेश गुप्ता ने नेशनल इन्टीग्रेशन कान्फरेन्स में स्वीकृत हुए कोड आफ कन्डक्ट के बारे में कहा है, वे उसको भूल गये है ऐसा मालूम पड़ता है । उसमें कहा गया था कि :

"No Party should indulge in any activity which would aggravate existing differences or create mutual hatred or cause tension between different castes and communities, religious or linguistic."

तो मेरा यह निवेदन है कि यह प्रस्ताव इस कोड आफ कन्डक्ट के खिलाफ़ है । ग्रीवैन्सेज हो सकते हैं किन्तु उन के लिये हमारे पास मशीनरी है । राष्ट्रपति जी के अलावा, अब यहां पर नेशनल इन्टीग्रेशन कौंसिल है जिस में सब प्रकार के लोग हैं । सिखों के ग्रीवैन्सेज के लिये दास कमीशन नियुक्त हुआ है जिस के सामने अकाली सिख जो

[श्री पां० ना० राजभोज]

ग्रीवैन्सेज के बारे में शोर करते हैं वे नहीं आ रहे हैं ।

तीसरे प्रकार के माइनोरिटीज हैं सामाजिक या आर्थिक जिनमें शिडयूल्ड कास्ट के लोगों का समावेश होता है । उनके लिए बहुत कुछ हो रहा है हमारे गृह मंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक इन लोगों को ऊंचे स्तर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं । एक राज्य में मुख्य मंत्री तथा केन्द्र सरकार में भी दो तीन मंत्री शिडयूल्ड कास्ट के हैं । उनको समाज से इन्टीग्रेट करने की कोशिश हो रही है । एक स्पेशल एजेन्सी शैडयूल्ड कास्ट कमिशनर के रूप में काम कर रही है । उसकी रिपोर्ट पर हर साल यहां बहस होती है और उस पर हम अपनी सूचना करते हैं और सरकार उसको अमल में लाने का प्रयत्न करती है । मैं आशा करता हूं कि वह प्रगति इतनी हो जायेगी कि शैडयूल्ड कास्ट में से गवर्नर, एम्बेसेडर, वगैरह तो बनेंगे ही किन्तु गांधी जी का स्वप्न कि एक हरिजन राष्ट्राध्यक्ष होना चाहिये, वह भी सफल होगा ।

चौथे प्रकार की माइनोरिटीज हैं शैडयूल्ड ट्राइब्ज, आदिवासी वगैरह की--- जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हैं । किन्तु उनको कल्चरल माइनोरिटी कहना उचित होगा । उन के लिए भी आज प्रयत्न हो रहे हैं । एक कमीशन नियुक्त हुआ था ढेबर भाई की अध्यक्षता में । उसने कई सिफारिशें की हैं, जिस में से एक ट्राइबल कमिशनर नियुक्त करने की बात है । उस पर सरकार कार्यवाही करेगी और उन के ग्रीवैन्सेज भी दूर किये जायेंगे । उसके लिये भी स्पेशल माइनोरिटी कमीशन की जरूरत नहीं है । उन के ग्रीवन्सेज हम कैसे दूर करेंगे इस के बारे में शैडयूल्ड एरियाज तथा शैडयूल्ड ट्राइब्ज कमीशन की रिपोर्ट के पृष्ठ ६ पर लिखा है । मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता किन्तु मेरी प्रार्थना है कि यह प्रस्ताव प्रेस न किया जाय । कई बातों से हम एग्री करते हैं किन्तु उसकी रेमेडी जो सजेस्ट की है वह नहीं है । जब तक मुस्लिम लीग के लोग भारत को अपना देश नहीं मानते तब तक ये ग्रीवैन्सेज जिंदा रहेंगे । हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि पाकिस्तान में हिन्दू माइनोरिटीज को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता । उससे तो यहां मुस्लिम माइनोरिटीज की पोजिशन कई गुना अच्छी है । संविधान में उनको फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं । उर्दू भाषा को अन्य भाषाओं के मुताबिक मान दिया जाता है लेकिन जो ग्रीवैन्सेज हैं उन के लिये अन्य मशीनरी इस्तेमाल की जाये तथा जो माइनोरिटीज कमीशनर हैं उनके अधिकार को तथा क्षेत्र को बढ़ाया जाये ताकि वे इन्डिविजुअल शिकायतों की तरफ ध्यान देकर उनको दूर कर सकें । मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर अमल किया जायेगा ।

श्री राम सहाय : (मध्य प्रदेश) : उप-सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि महज प्रोपेगेन्डा की दृष्टि से इसको यहां लाया गया है । हमारा संविधान ऐसा है, कि उस में अल्पसंख्यकों का सवाल पैदा नहीं होता है, बल्कि उस में मनुष्य मात्र के राइट्स की, हकों की, हिफाजत की गई है । हमारे शासन का और विशेषकर कांग्रेस पार्टी का सदा यह उद्देश्य रहा है कि अल्पसंख्यकों के हितों का भली प्रकार से ध्यान रखा जाय । इस बारे में जहां शासन बहुत सचेत है वहां कांग्रेस आर्गेनाइजेशन भी पूरी तरह प्रयत्नशील है । इस समय जो प्रस्ताव हमारे सामने लाया गया है वह एक प्रोपेगेन्डा की दृष्टि से लाया गया है क्योंकि चुनाव बहुत जल्दी सारे देश में होने वाले हैं । लेकिन मैं प्रस्तावक महोदय से यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज से बहुत समय पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इसी मकसद के लिए एक कमेटी मुकर्रर

की थी जिसकी चैयरमैन श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं। उन्होंने इस मसले पर और इसी प्रकार के दूसरे मसलों पर बहुत गम्भीरता-पूर्वक और अच्छी तरह से विचार किया और इस कमेटी की कई मीटिंग्स इस बारे में हुईं। इतना ही नहीं, इसके बाद हमारे पूज्य श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने चीफ मिनिस्टरों की एक बहुत बड़ी कान्फ्रेन्स बुलाई ताकि इस मसले पर सब चीफ मिनिस्टरों के विचार मालूम किये जा सकें। इसके बाद उन्होंने देश के विद्वानों और बड़े बड़े लोगों की कान्फ्रेंस बुलाई और इस में देश के एजुकेशनिस्ट और दूसरे बड़े बड़े लोग सम्मिलित हुए। मुझे भी उस कान्फ्रेन्स में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं समझता हूं कि उस कान्फ्रेंस में जिस तरह से विचार किया गया उस से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव में जिस तरह का आयोग नियुक्त करने की मांग की गई है वह आवश्यक नही है। मेरा तो यह ख्याल है कि इस प्रकार की एक कमेटी कांग्रेस की ओर से बनी हुई है और उस के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसी तरह की एक कमेटी बनाई है जो इस तरह के सवालों पर गौर करेगी और अल्पसंख्यकों के हित के लिए जो कुछ भी करना जरूरी होगा वह करेगी। जहां तक हरिजन, आदिवासी और मुसलमानों का सवाल है, उन के बारे में काफी विचार पिछली बड़ी मीटिंग में किया गया था। हमारे देश में एजूकेशन का जो सिस्टम है वह ऐसा है कि किसी भी विद्यार्थी को चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो उसको अपनी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। जहां तक अल्पसंख्यकों का सवाल है उन के लड़कों को भी पढ़ाई के मामले में हर प्रकार की सुविधा मिली हुई है। जहां तक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सवाल है उन के द्वारा भी किसी प्रकार की बाधा किसी जाति-विशेष के लिए नहीं की जाती है और सब लोगों को बराबर उन्नति का अवसर यह कमीशन प्रदान करता है।

यह प्रस्ताव जो रखा गया है वह एक बेकार सा है। मुझे अफसोस है कि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले महोदय इस समय हाउस में तशरीफ़ नहीं रखते हैं। मैं उन से यह अर्ज करना चाहता हूं कि बजाये इस के कि वे इस प्रकार के प्रस्ताव को हाउस में लायें, उन्हें इस तरह की बात को अपनी पार्टी में रखना चाहिये था और देश में इस तरह का वातावरण पैदा करना चाहिये था कि जिस से लोगों को मालूम हो कि हमें अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिये। मेरा तो यह निश्चय मत है कि अभी हाल में अल्पसंख्यकों के साथ--विशेषकर मुसलमानों के साथ--जो दिक्कतें पेश आई हैं उस में सब पार्टी के लोग सहयोग करते, ऐसा वातावरण पैदा करते कि सब लोगों को मिल कर रहना चाहिये तो इस तरह की स्थिति पैदा न होती। मेरा अब भी विश्वास है कि अगर हमारे दोस्त और सब पार्टी के लोग जनता में अच्छे विश्वास के साथ और अपना कर्त्तव्य समझ कर यह बात कहें कि सब जाति के लोगों को मिलकर रहना है और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरह का प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार का जहां तक सवाल है वह इस बारे में अच्छे से अच्छा कार्य बराबर करती चली जा रही है। जहां तक जनता के दिलों से इस तरह की भावना दूर करने का सवाल है इसमें सब पार्टियों के लोगों को मिलकर काम करना चाहिये। सरकार तो इस तरह का कार्य कर रही है और वह भी इस कार्य में जितना सहयोग होगा, देगी। मेरा अंत में यही निवेदन है

[श्री राम सहाय]

कि इस समय सदन में जिस प्रकार का प्रस्ताव लाया गया है वह मुनासिब नहीं है और इस समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

شریمتی انیس قدوائی (اتر پردیش): جناب ڈپٹی چیرمین صاحب - یہ جو پرستاو اپوزیشن ممبر کی طرف سے ہاؤس میں آیا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ وقت کے خلاف کوئی چیز ہے - اگرچہ یہ اپوزیشن کی طرف سے آیا ہے مگر یہ واقعہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ کافی دنوں سے سب کے لئے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے - گورنمنٹ کی توجہ اس بات کی طرف ہے اور جتنے بھی پبلک ورکر ہیں وہ بھی اس بارے میں سوچ رہے ہیں- مہینوں سے ہم لوگ بھی اس مسئلہ پر کافی سوچ بچار کر چکے ہیں - گورنمنٹ اس بارے میں پوری کوشش کر رہی ہے اور پنڈت جی نے جو کانفرنس حال میں بلائی تھی اس میں بھی اس معاملہ پر پوری طرح غور کیا گیا اور بہت سے سجھاو رکھے گئے تاکہ اس صورت حال سے کس طرح نپٹا جا سکے - لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف اس وقت شری رام سہائے جی نے زیادہ توجہ نہیں دی ہے - وہ اس کو ایک چھوٹا سا معاملہ سمجھے ہوئے ہیں - اس کے ساتھ ہی ساتھ شری راجا بھوج کا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ صرف مسلمانوں کا ہے جو کہ ایک غلط بات ہے - اس ملک میں کئی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور کئی طرح کی مائناریٹیز یہاں رہتی ہیں - مائناریٹیز کا معاملہ کوئی دس پانچ برس کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے - یہ ایک بہت پرانی بیماری ہے اور اس بیماری کو دور کرنیکے لئے جتنی کوشش اب تک کانگریس نے کی ہے وہ پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی ہے - اور نہ گورنمنٹ پوری طرح کامیاب ہوسکی ہے - اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر قسم کے جھگڑے فساد اور دوسری چیزیں اب بھی ہوتی رہتی ہیں - اس لئے اگر ہم اس مسئلہ پر ٹھنڈے دل سے غور کر لیں تو اچھا ہی ہوگا - آیا یہ سوچنا کہ مائناریٹیز کے مسئلہ کو طے کرنے کے لئے ایک کمیشن بنایا جائے اور ان کی دیکھ بھال کے لئے سینٹر یا اسٹیٹ میں مستقل کوئی اسی طرح کی چیز بنادی جائے کارآمد ثابت ہوگی- یا اس طرح کی کوئی دوسری چیز بنائی جائے - میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں جتنی قومیں بستی ہیں، جتنے لوگ رہتے ہیں، ان کو قانون اور وہاں میں برابر کے حق دئے گئے ہیں - اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے، کہ جتنے ہمارے ملک کے بڑے لوگ ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہر شہری کو برابر کا حق دیا جانا چاہئیے اور ان کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جانا چاہئیے- لیکن کوئی کمی ہماری سوسائیٹی میں

سے یہاں اپنا کام شروع کیا اور وہ ہندوستان کا نظام بالکل دوسرے ڈھنگ سے بنانا چاہتی تھیں - انہیں قیمو کریسی پر بھروسہ نہیں ہے - انہوں نے جمہوریت کو آجتک نہیں مانا - وہ صرف زبان سے کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت کو مانتے ہیں لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ کچھ ایسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے قیموکریسی کو کسی طرح بھی آجتک قبول نہیں کیا ہے- وہ ہندوستان میں ایک دوسری طرح سےحکومت کا نظام قائم کرنا چاہتی ہیں- اس لئے ہندو پبلک کی سپورٹ لینے کے لئے ضروری تھا کہ وہ ہندو پبلک کا رخ مسلمانوں کی طرف پھیر کر ہندو مسلم سوال کھڑا کریں اور ہندوستان میں بلوے کرائیں - اب یہ کہہ دینا کہ ایک کمیشن بن جائے اور وہ اس معاملہ پر غور کرے اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے - یہ صرف مائناریٹیز کے حق کا مسئلہ نہیں ہے - جب تک کہ گورنمنٹ پوری طرح سے اس پر غور نہیں کریگی اور ہوم منسٹر کی پوری توجہ اس مسئلہ پر نہیں ہوگی تب تک یہ معاملہ طے نہیں ہو سکتا۔ بے شک مسلمانوں کو یا دوسری مائناریٹیز کو شکایتیں ہیں اس لئے کہ گورنمنٹ کی مشینری میں کمزوری ہے جس کی وجہ سے نیچے سے معاملے طے نہیں ہوتے ہیں اور قانون میں جتنے بھی تحفظات دئے گئے ہیں یا جتنے بھی حقوق دئے گئے ہیں ان کا پوری طرح یا گورنمنٹ کی مشینری میں ایسی ہے کہ جو اس کام کو پورا نہیں ہونے دیتی ہے یا وقت پر اس چیز کو پورا نہیں کرتی - یہی وجہ ہے کہ ملک میں آزادی آئے چودہ برس ہوگئے ہیں لیکن یہ کام ابھی تک پورا نہیں ہو سکا ہے -

مجھے یہ کہنے میں پس و پیش نہیں ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی بہت بڑی اقلیت ہے اور وہ سب سے بڑی اقلیت ہے - اس کے علاوہ یہاں کرسچن بھی ہیں اور جیسا کہ ابھی شری راجا بھوج نے کہا کہ ایک نئی اقلیت بدھسٹ کی بھی پیدا ہوگئی ہے -لیکن وہ پہلے مائناریٹی میں نہیں سمجھے جاتے تھے بلکہ ہندو مذہب کا ایک جز سمجھے جاتے تھے - اب وہ مائناریٹی کے روپ میں سامنے آئے ہیں - اسی طرح ہریجنوں کا معاملہ ہے - مسلمانوں کا جہاں تک سوال ہے ہندو مسلمان بلووں کی وجہ سے اس کو زیادہ اہمیت دیدی گئی ہے - جیسا کہ ابھی حال میں مدھیہ پردیش میں ہوا یو - پی کے ضلعوں میں ہوا تھا اس کی وجہ سے یہ مسئلہ اور اہم ہو گیا ہے - لیکن اس چیز کو ہندو مسلمان کا سوال بنا کر دیکھنا غلط ہے - اس لئے یہ غلط ہے کہ دو ایک پارٹیاں ایک نئی ایڈیالوجی لیکر سامنے آئیں - انہوں نے پندرہ سولہ سال

شریمتی انیس قدوائی : میرا خیال ہے کہ اگر ری ہیبیلیٹیشن کے لئے منسٹر مقرر کیا جا سکتا ہے - اگر انڈسٹریز کے لئے منسٹر مقرر کیا جا سکتا ہے - اگر تمام مسائل کے لئے ڈیپارٹمنٹ قائم کئے جا سکتے ہیں تو صرف مائناریٹیز کے لئے بھی ایک ڈپٹی منسٹر مقرر کیا جا سکتا ہے تاکہ قانون میں جو بھی حقوق مائناریٹیز کو دئے گئے ہیں ان پر پوری طرح سے وہ عمل کرا سکے -

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर माइनौरिटीज़ अफेयर्स के भी मिनिस्टर हैं ।

شریمتی انیس قدوائی - پہلے لا منسٹر مائناریٹیز افیر کے بھی ذمہ دار تھے - مسٹر بسواس کے بعد کوئی ایسا سوال باقی نہیں رہا - مسٹر بسواس کے ہی سپرد مائناریٹیز کے معاملے کئے گئے تھے - مسلمانوں کے لئے اور دوسری مائناریٹیز کے لئے اس وقت سب سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ آخر وہ کس کے سامنے اپنے مسائل رکھیں - وہ اپنے مسائل چیف منسٹر تک پہونچائیں یا ہوم منسٹر تک پہونچائیں یا جو لنگوسٹک مائناریٹیز کے کمشنر مقرر ہوئے ہیں ان کے پاس لے جائیں - لیکن دس جگہ جانے سے یہ اچھا ہے کہ ہوم منسٹری جس سے متعلق ملک کا انتظام ہے ، جس سے متعلق پولیس ہے ، جس سے متعلق دوسرے کام ہیں اسی سے متعلق

[شریمتی انیس قدوائی]

سے امپلیمینٹیشن نہیں ہوتا ہے - ہوم منسٹری ہی ان کی جان اور مال عزت اور ہر چیز کی حفاظت کر سکتی ہے - اس لئے آپ چاہے جیسا بھی پاررفل کمیشن بنائیں، چاہے جو بھی کریں مگر آپ اس مسئلہ کو کسی طرح سے طے نہیں کر سکتے - میرا تو ایسا خیال ہے کہ اس کام کے لئے اگر ہوم منسٹری میں ایک ڈپٹی منسٹر مقرر ہو اور اس کے سپرد یہ کام ہو تو وہ اس معاملہ کو طے کر سکتا ہے اور ان چیزوں کو پوری طرح سے دیکھ سکتا ہے - کیونکہ اس میں جان و مال، عزت اور ہر چیز کی حفاظت کا سوال آ جاتا ہے - آپ دیکھئے کہ رائے پور میں جو جھگڑا ہوا وہ عیسائیوں اور ہندوؤں میں ہوا- جبلپور میں ایک مرتبہ جینیوں اور ہندوؤں میں ہوا - آسام میں آسامیوں اور بنگالیوں میں جھگڑا ہوا - اس طرح سے کئی جگہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں بھی جھگڑے ہوئے - اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مائناریٹیز کو حق دیدینے سے کسی کو اطمینان نہیں ہوگا - اصل چیز تو جو جھگڑا کرنے والی پارٹیز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی ہے اور تب ہی سب کو اطمینان ہوگا -

डा० श्रीमती सीता परमानन्द (मध्य प्रदेश): क्या एक एक मामले के लिए डिप्टी मिनिस्टर मुकर्रर करना चाहिये

تک پہونچا سکتا ہے - آج صرف گورنمنٹ تک شکایتیں پہونچانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قانون میں جتنے بھی حقوق دئے گئے ہیں ، جتنے بھی تحفظات دئے گئے ہیں ان کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے - اس لئے میں سمجھتی ہوں کہ یہ پرستاو بالکل بیکار ہے اور اس سے کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے - لیکن گورنمنٹ کو اس طرف توجہ ضرور کرنی چاہیئے اور پوری طرح توجہ کرنی چاہیئے - گورنمنٹ کی تھوڑی سی توجہ اس طرف ہو بھی چکی ہے کیونکہ جو سرکلر ابھی حال میں ہوم منسٹری کی طرف سے ڈسٹرکٹ اور صوبے کی گورنمنٹوں کو اور پولیس وغیرہ کو جاری ہوا ہے وہ ایک اچھا قدم ہے - جبلپور کے بعد میں نے علی‌گڑھ میں جو کچھ دیکھا ہے اس سے بھی تھوڑی سی تسکین ہوتی ہے کہ وہاں گورنمنٹ نے پوری طرح سے توجہ کی ہے - میں یہ چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ مائناریٹیز کی جان و مال، عزت اور ہر چیز کی حفاظت کی پوری ذمہ‌داری لے -

جہاں تک ملازمتوں اور دوسری شکایتوں کا سوال ہے میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس طرف گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑی بھی توجہ دی گئی تو کسی نئے قانون یا کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی - گورنمنٹ خود ہی اس معاملہ کو دیکھ کر حل مائناریٹیز کے معاملے ہوں - کی کمیشن سے ان کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے ہیں -

صورت یہ ہے کہ ان چند سالوں کے اندر جن سنگھ اور دوسری پارٹیز کی اکٹویٹیز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے لئے سچ مچ خطرات پیدا ہو گئے ہیں - آپ یہی نہیں سمجھئے کہ صرف مسلمانوں کو ہی خطرے پیدا ہوئے ہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ جتنی بھی مائناریٹیز اس وقت ملک میں موجود ہیں کسی نہ کسی بہانے سے ان سب کے خلاف کوئی نہ کوئی چیز اٹھائی جا رہی ہے - کبھی ایجوکیشن کا معاملہ لیکر کرشچین کے خلاف سوال اٹھایا جاتا ہے ، کبھی عبادت گاہوں کا معاملہ اٹھایا جاتا ہے اور کبھی کوئی مسئلہ چھیڑ دیا جاتا ہے - یہ مسئلے ایسے ہیں جن کو ہوم منسٹری ہی حل کر سکتی ہے کوئی کمیشن حل نہیں کر سکتا ہے - جو بھی کمیشن بنیگا وہ بالکل بیکار ثابت ہوگا - وہ اسی طرح سے ہوگا جیسے کہ لنگرسنگ مائناریٹیز کے لئے کمشنر مقرر کیا گیا جو اپنی رپورٹ سال بہ سال پیش کر دیتا ہے ، جس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں ، جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے اور وہ کسی طرح سے ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے - وہ صرف ان کی شکایتیں گورنمنٹ تک

[شریمتی انیس قدوائی]

کر سکتی ہے کہ ہمارے جو افسر ہیں وہ قانون میں جو احکام دئے گئے ہیں ان پر پوری پابندی سے عمل کر رہے ہیں یا نہیں - جو کچھ بھی گڑبڑ ہوتا ہے - وہ نیچے سے ہوتا ہے - مجھے یقین ہے کہ کبھی اوپر سے ایسے سرکلر ایشو نہیں ہوئے ہونگے کہ کسی شخص کی حق تلفی کی جائے اور کسی کی جائیداری کی جائے - ایسے جو بھی معاملے ہوتے ہیں وہ مقامی طور پر ہوتے ہیں اور ان کو اسٹیٹ گورنمنٹ پوری طرح سے دیکھ سکتی ہے - یا ہوم منسٹر کے سپرد اس معاملہ کو کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس کو اچھی طرح سے طے کر سکتا ہے -

میں ان الفاظ کے ساتھ اس ریزولیوشن کی مخالفت کرتی ہوں -

†[**श्रीमती अनीस किदवई** (उत्तर प्रदेश): जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, यह जो प्रस्ताव अपोजीशन मेम्बर की तरफ से हाउस में आया है उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह वक्त के खिलाफ कोई चीज है । अगरचे यह अपोजीशन की तरफ से आया है, यह वाक्या है कि यह मसला ऐसा है कि काफी दिनों से सब के लिये परेशानी का बायस बना हुआ है । गवर्नमेंट को तवज्जुह इस बात की तरफ है और जितने भी पब्लिक वर्कर हैं वह भी इस बारे में सोच रहे हैं । महीनों से हम लोग भी इस मसले पर काफी सोच विचार कर चुके हैं । गवर्नमेंट इस बारे में पूरी कोशिश कर रही है और पंडित जी ने जो कांफ्रेंस हाल ही में बुलाई थी, उसमें भी इस मामला पर पूरी तरह गौर किया गया और बहुत से सुझाव रखे गये ताकि इस सूरते हाल से किस तरह निबटा जा सके । लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी तरफ इस वक्त श्री राम सहाय जी ने ज्यादा तवज्जुह नहीं दी है । वह इसको एक छोटा सा मामला समझे हुये हैं । इसके साथ ही साथ श्री राजभोज का यह ख्याल है कि यह मामला सिर्फ मुसलमानों का है, जो कि एक गलत बात है । इस मुल्क में कई मजाहब के लोग रहते हैं और कई तरह की माइनौरिटीज यहां रहती हैं । माइनौरिटीज का मामला कोई दस पांच वर्ष का पैदा किया हुआ नहीं है । यह बहुत पुरानी बीमारी है । और इस बीमारी को दूर करने के लिये जितनी कोशिश कांग्रेस ने अब तक की है वह पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकी है । और न गवर्नमेंट पूरी तरह से कामयाब हो सकी है । इस तरह से इसका नतीजा यह हुआ कि हर किस्म के झगड़े फसाद और दूसरी चीजें अब भी होती रहती हैं । इसलिये अगर हम इस मसले पर ठंडे दिल से गौर कर लें तो अच्छा ही होगा । आया यह सोचना कि माइनौरिटीज के मसले को तय करने के लिये एक कमीशन बनाया जाये और उनकी देखभाल के लिये सेंटर या स्टेट में मुस्तकिल कोई इसी तरह की चीज बना दी जाये, कारामद साबित होगा । या इस तरह की कोई दूसरी चीज बना दी जाय । तो मेरा ऐसा ख्याल है कि हिन्दुस्तान में जितनी कौमें बसती हैं, जितने लोग रहते हैं, उनको कानून और विधान में बराबर के हक दिये गये हैं । इस बात में भी कोई शक नहीं हो सकता है कि जितने हमारे मुल्क के बड़े लोग हैं वह भी यही चाहते हैं कि हर शहरी को बराबर का हक दिया जाना चाहिये और उनके साथ बराबर का सुलूक किया जाना चाहिये । लेकिन कोई कमी हमारी सोसाइटी में या गवर्नमेंट की मशीनरी में ऐसी है जो इस काम को पूरा नहीं होने देती है या वक्त पर इस चीज को पूरा नहीं करती । यही वजह है कि मुल्क में आजादी आये १४ वर्ष हो गये

†[ ] English translation.

हैं लेकिन यह काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है।

मुझे यह कहने में पशोपेश नहीं है कि हिन्दुस्तान में मुसलमानों की बड़ी अकलियत है और वह सब से बड़ी अकलियत है। इसके अलावा यहां क्रिश्चियन भी हैं और जैसा कि अभी राजभोज ने कहा कि एक नयी अकलियत बुद्धिस्ट को भी पैदा हो गई है। लेकिन पहले वह माइनौरिटीज में नहीं समझे जाते थे, बल्कि हिन्दू मजहब का एक जुज समझ जाते थे। अब वह माइनौरिटी के रूप में सामने आये हैं। इसी तरह हरिजनों का मामला है। मुसलमानों का जहां तक सवाल है हिन्दू-मुसलमान बलवों की वजह से इसको ज्यादा अहमियत दे दी गई है। जैसा कि अभी हाल में मध्य प्रदेश में हुआ या यू० पी० के जिलों में हुआ था। उसकी वजह से यह मसला और अहम हो गया है। लेकिन इस चीज को हिन्दू मुसलमान का सवाल बनाकर देखना गलत है। दो एक पार्टियां एक नई आइडियालौजी लेकर सामने आई हैं। उन्होंने १५-१६ साल से यहां अपना काम शुरू किया और वह हिन्दुस्तान का निजाम बिलकुल दूसरे ढंग से बनाना चाहती थीं। उन्हें डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं है। उन्होंने जम्हूरियत को आज तक नहीं माना। वह सिर्फ जुबान से कहती हैं कि हम जम्हूरियत को मानते हैं लेकिन इसमें शक नहीं कि कुछ ऐसी पार्टीज हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को किसी तरह भी आज तक कबूल नहीं किया है। वह हिन्दुस्तान में एक दूसरी तरह से हुकूमत का निजाम कायम करना चाहती हैं। इसलिये हिन्दू पब्लिक की सपोर्ट लेने के लिये जरूरी था कि वह हिन्दू पब्लिक का रुख मुसलमानों की तरफ फेरकर हिन्दू-मुस्लिम सवाल खड़ा करें और हिन्दुस्तान में बलवे करायें। अब यह कह देना कि एक कमीशन बन जाये और वह इस मसला पर गौरकरे, इससे यह मसला हल नहीं हो सकता है। यह सिर्फ माइनौरिटीज के हक का मसला नहीं है। जब तक कि गवर्नमेंट पूरी तरह से गौर नहीं करेगी और होम मिनिस्टर की पूरी तवज्जुह इस मसले पर नहीं होगी, तब तक यह मामला तय नहीं हो सकता, बेशक मुसलमानों को या दूसरी माइनौरिटीज को शिकायतें हैं। इसलिये कि गवर्नमेंट की मशीनरी में कमजोरी है जिसकी वजह से नीचे से मामले तय नहीं होते हैं और कानून में जितने भी तहफ्फजात दिये गये हैं या जितने भी हुकूक दिये गये हैं, उनका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, होम मिनिस्ट्री ही इनकी जान और माल, इज्जत और हर चीज की हिफाजत कर सकती है। इसलिये आप चाहे जैसा भी पावरफुल कमीशन बनायें, चाहे जो भी करें आप इस मसला को किसी तरह से तय नहीं कर सकते। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि इस काम के लिये अगर होम मिनिस्ट्री में एक डिप्टी मिनिस्टर मुकर्रर हो और उसके सिपुर्द यह काम हो तो वह इस मामला को तय कर सकता है और इन चीजों को पूरी तरह से देख सकता; है क्योंकि जान व माल, इज्जत और हर चीज की हिफाजत का सवाल आता है। आप देखिये कि रायपुर में जो झगड़ा हुआ, वह ईसाइयों और हिन्दुओं में हुआ। जबलपुर में एक मर्तबा जैनियों और हिन्दुओं में हुआ। आसाम में आसामियों और बंगालियों में झगड़ा हुआ। इसी तरह से कई जगह हिन्दुओं और मुसलमानों में भी झगड़े हुये। इसका मतलब यह है कि सिर्फ माइनौरिटी को हक दे देने से किसी को इत्मीनान नहीं होगा। असल चीज तो जो झगड़ा करने वाली पार्टीज हैं उनको कंट्रोल करने की ही है और तब ही सब को इत्मीनान होगा।

डा० श्रीमती सीता परमानन्द (मध्य प्रदेश) : क्या एक एक मामले के लिये डिप्टी मिनिस्टर मुकर्रर करना चाहिये ?

श्रीमती अनीस किदवई : मेरा ख्याल है कि अगर रिहैबिलिटेशन के लिये मिनिस्टर मुकर्रर किया जा सकता है, अगर इंडस्ट्रीज के लिये मिनिस्टर मुकर्रर किया जा सकता है, अगर तमाम मसायल के लिये डिपार्टमेंट कायम किये

[श्रीमती अनीस किदवई]

जा सकते हैं तो सिर्फ माइनौरिटीज के लिये भी एक डिप्टी मिनिस्टर मुकर्रर किया जा सकता है, ताकि कानून में जो भी हुकूक माइनौरिटीज को दिये गये हैं, उन पर पूरी तरह से वह अमल करा सके।

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर माइनौरिटीज अफेयर्स के भी मिनिस्टर हैं।

श्रीमती अनीस किदवई : पहले ला मिनिस्टर माइनौरिटीज अफेयर के भी जिम्मेवार थे। मि० विश्वास के बाद कोई ऐसा मसला बाकी नहीं रहा ? मिनिस्टर विश्वास के ही सिपुर्द माइनौरिटीज के मामले किये गये थे। मुसलमानों के लिये और दूसरी माइनौरिटीज के लिये इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल यह है कि आखिर वह किसके सामने अपने मसायल रखें ? अब वह अपने मसायल चीफ मिनिस्टर तक पहुंचायें या होम मिनिस्टर तक पहुंचायें या जो लिंग्विस्टिक माइनौरिटीज के कमिश्नर मुकर्रर हुये हैं उनके पास ले जायें? लेकिन १० जगह जाने से यह अच्छा है कि होम मिनिस्ट्री जिससे मुतल्लिक मुल्क का इन्तजाम है, जिससे मुतल्लिक पुलिस है, जिससे मुतल्लिक दूसरे काम हैं उसी से मुतल्लिक माइनौरिटीज के मामले हों। किसी कमीशन से उनके मामले हल नही हो सकते हैं।

सूरत यह है कि इन चन्द सवालों के अन्दर जन-संघ और दूसरी पार्टीज की एक्टिविटीज इतनी बढ़ गई हैं कि उसकी वजह से मुसलमानों के लिये सचमुच खतरात पैदा हो गये हैं। आप यह नहीं समझिये कि सिर्फ मुसलमानों को ही खतरे पैदा हुये हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि जितनी भी माइनौरिटीज मुल्क में इस वक्त मौजूद हैं किसी न किसी बहाने से उन सबके खिलाफ कोई न कोई चीज उठाई जा रही है। कभी एजूकेशन का मामला लेकर क्रिश्चियन के खिलाफ सवाल उठाया जाता है, कभी इबादतगाहों का मामला उठाया जाता है और कभी कोई मसला छेड़ दिया जाता है। यह मसले ऐसे हैं, जिनको होम मिनिस्ट्री ही हल कर सकती है, कोई कमीशन हल नही कर सकता है। जो भी कमीशन बनेगा वह बिल्कुल बेकार साबित होगा। वह इसी तरह से होगा जैसे कि लिंग्विस्टिक माइनौरिटीज के लिये कमिश्नर मुकर्रर किया गया है जो अपनी रिपोर्ट साल ब साल पेश कर देता है। जिसके पास कोई अख्तियारात नहीं हैं, जिसके पास कोई पावर नहीं है और वह किसी तरह से उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। वह सिर्फ उनकी शिकायतें गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता है। आज सिर्फ गवर्नमेंट तक शिकायतें पहुंचाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कानून में जितने भी हकूक दिये गये हैं, जितने भी तहफ्फजात दिये गये हैं उनको अमल में लाने की जरूरत है, इसलिये मैं समझती हूं कि यह प्रस्ताव बिल्कुल बेकार है और इससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जुह जरूर करनी चाहिये और पूरी तवज्जुह करनी चाहिये। गवर्नमेंट की थोड़ी सी तवज्जुह इस तरफ हो भी चुकी है; क्योंकि जो सरकुलर अभी हाल में होम मिनिस्ट्री की तरफ से डिस्ट्रिक्ट और सूबे की गवर्नमेंटों को और पुलिस वगैरा को जारी हुआ है, वह एक अच्छा कदम है। जबलपुर के बाद मैंने अलीगढ़ में जो कुछ देखा है, उससे भी थोड़ी सी तसकीन होती है कि गवर्नमेंट ने वहां पूरी तरह से तवज्जुह की है। मैं यह चाहती हूं कि गवर्नमेंट माइनौरिटीज की जान व माल व इज्जत और हर चीज की हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी ले ले।

जहां तक मुलाजमतों और दूसरी शिकायतों का सवाल है, मैं समझती हूं कि अगर इस तरफ गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी भी तवज्जुह दी गई तो किसी नये कानून या कमीशन बनाने की जरूरत नहीं होगी। गवर्नमेंट खुद ही इस मामले को यह देखकर हल कर सकती है कि हमारे जो अफसर हैं वह

कानून में जो अहकाम दिये गये हैं उन पर पूरी पाबन्दी से अमल कर रहे हैं या नहीं। जो कुछ भी गड़बड़ होता है वह नीचे से होता है। मुझे यकीन है कि कभी ऊपर से ऐसे सरकुलर इश्यू नहीं हुये होंगे कि किसी शख्स की हक तलफी की जाये और किसी की जानिबदारी की जाये। ऐसे जो भी मामले होते हैं वह मुकामी तौर पर होते हैं और उनको स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से देख सकती है या होम मिनिस्टर के सिपुर्द इस मामले को किया जाय तो मेरा ख्याल है कि वह भी इसको अच्छी तरह से तय कर सकता है।

मैं इन अलफाज के साथ इस रेजोल्यूशन की मुखालफत करती हूं।]

SHRI KRISHAN DUTT (Jammu and Kashmir): Mr. Deputy Chairman, the question of minorities in India is of the highest importance and unless the minorities have full faith in our national leaders and in our Governments, both at the Centre and at the State level, our country cannot progress. That is a fundamental thing in our national life. The minorities must always have full protection in all spheres—social, economic and political. Without protecting the minorities, our nation cannot go forward, the country cannot go forward. That is a fundamental fact in our country and in our national life. I entirely agree with Shrimati Anis Kidwai that the State Government and the Central Government must always remain vigilant and should always take effective steps to generate a sense of security, a sense of confidence in the political set-up of our country. Without that faith and confidence, I think all our efforts in the task of the building up of our national life and the reconstruction of our country cannot achieve success. The question of minorities goes to the root of the law and order question also. Therefore, we must give it the most serious thought and the utmost importance that we can give it. With all that, I think that the setting up of a permanent Minorities Commission of a statutory kind cannot achieve this purpose. That is my humble view. I would like to invite the hon. Members' attention to the constitutional guarantees that are to be found in our Constitution itself, namely, articles 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29 and 30, with regard to the protection of the minorities' rights and interests. These constitutional guarantees are quite adequate and sufficient for the protection of the rights and interests of the minorities. Moreover, we have got the High Courts and the Supreme Court invested with writ jurisdiction which can very adequately safeguard the implementation of the minorities' rights and interests. To safeguard the implementation of these provisions and to bring about the effective enforcement of these safeguards, it was considered necessary, on the basis of the Report of the States Reorganisation Commission, that a Minorities Commissioner should be appointed and this provision was incorporated in our Constitution in the shape of articles 350-A and 350-B. It is to some extent correct to say, as Shrimati Anis Kidwai has done, that this Commissioner simply focuses attention on the grievances and the disabilities which the minorities still have to face in our country. Merely bringing these grievances to light or to the attention of the authorities is not sufficient. What is important is their successful removal and the effective implementation of those safeguards. I heartily endorse the remedies suggested by Shrimati Kidwai that it is mainly and chiefly the function of the State Governments and the Central Government, and in particular, of the Home Ministry, to see that the minorities' interests and rights are always vigilantly guarded and effectively protected.

There is another objection to the setting up of such a Commission as is envisaged in the present Resolution. If we set up such a statutory commission, there will be conflict of authorities. We already have the States machinery and the Central machinery and also our

[Shri Krishan Dutt.]

President who is invested with the power to look after the rights and interests of minorities, under article 350-A and article 350-B. Therefore, the setting up of a statutory commission would be duplication of authorities and there will be conflict of jurisdiction. Therefore, on that account also, the setting up of a Minorities Commission of a permanent character is not proper and desirable.

There is another point which I would like to bring to the notice of the hon. Members of the House. India is wedded to the goal of having a secular pattern of society. To bring about such a society it is necessary that the natural process of assimilation and national integration should not be hampered in any way. To create a commission of the nature contemplated in this Resolution would in my opinion, create a barrier—and a permanent barrier—to the working of that process of national assimilation and national integration. We should not in any way do anything which would perpetuate a sense of separatism, or shall I say, do something which would come in the way of the natural growth of an all-India consciousness and a one-nation consciousness. That is a process which we should help by all our efforts. The recent conference on national integration, I would submit, made very valuable contributions to the advancement of that process. Therefore, in my humble opinion, the setting up of such a commission is not called for. It is not essential for the purpose for which it is sought to set up such a commission. That purpose can be better served by working at social levels, by working at economic levels in such a manner that all sections of our countrymen, irrespective of their caste, creed or religion, may benefit equally and may be made to feel that they are not discriminated against, either politically, economically or socially. That is something which requires a change in the psychology of our nation. Each and every individual in India should try to enlarge his mental horizon and create in himself an enlarged view of his responsibilities to the nation. He should try to think and feel that all the inhabitants of India are like himself. Anything that pinches him, he should scrupulously avoid doing to others. If that point is always kept in view by our countrymen, I think, most of the troubles which arise due to these differences of caste, creed and religion can disappear. Government alone cannot do everything. It is the people who have to contribute most in lifting the country out of the morass of these social disabilities and social conflicts that often make their appearance here and there in our country. That is of basic importance. No doubt, governmental action is most necessary to curb these evil tendencies of separatism and to solve the problems of law and order. Such erruptions of untoward voilence and untoward incidents must be severely dealt with and all our officers, down to the lowest level, should feel that it is their responsibility to see that every one of our countrymen is made to feel that he is secure, that his life, honour and liberty are perfectly secure and safe in the hands of the administration. That sense must be created at all costs. We must work diligently and to the utmost of our capacity to achieve that desirable and happy state of affairs. With these words, while I do not at all underrate the importance of the minorities question, I humbly have to submit that the remedy provided or sought to be got through the setting up of a Commission is not at all necessary, desirable or proper.

SHRI N. SRI RAMA REDDY (Mysore): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to oppose this motion. Sir, it is known by now all over the world that ours is a secular State and that we are great believers in democracy. These two things by themselves give a lie direct to the constitution of a Commission which is proposed in this Resolution. We have had the experience of running a sovereign independent Government in this country for the last 14 years and what has that experience

taught us? It has taught us that we, true to our professions, true to our Constitution, have carried on the Government of the country faithfully and honestly and have also earned the approbation of the whole world. We have been quite true to our professions. Nobody can say that any minority group in this country has been treated badly. Sir, right from the days of our independence in the year 1947 it can be seen how the idea of the secular State has been instilled in everybody's mind. Even during those troublous days of 1947 both Hindus and Muslims and other minorities, everybody in fact, tried their utmost to live amicably and not to create confusion that has been created on the other side of the border. There were instances when even during those troublous days the majority community has gone to the rescue of the minority community, and fights have taken place. Numerous such instances could be seen, glorious instances to prove how our secular State is functioning in this country. If the problem of minorities is looked at in contrast with the situation obtaining in our neighbouring State, people might get a bit nervous but if forget for a moment the situation obtaining in our neighbouring State and if we take facts as they obtain in our country no minority group can say that the law of the land is not giving protection to the honour, dignity and self-respect of the group. Sir, it is very unfortunate that a person who does not believe either in caste or creed or religion or God should bring forward a Resolution of this kind. I see, Sir, a sinister motive in a Resolution of this kind when just at the time of the general elections when each according to his belief, each according to his principle, each according to his political conscience, has got to give his vote, such an idea of a majority class and a minority class is attempted to be introduced in the country by this Resolution. It does not become a Communist to introduce a Resolution like this in this House. We do not believe in minorities; we are a nation; we are an independent nation; we belong to one nation and nobody is a minority, nobody is a majority. Our law is uniform for all. We are having the proud privilege of declaring before the world that it is the rule of law that is obtaining in this great country of ours today. Nobody is discriminated against. Sir, if we stretch our imagination, if we go round the country, we will know what is happening. In my own place, Bangalore City, in a central square a beautiful mosque is coming up. Whoever is objecting to it? Nobody; not a single person out of the entire 16 lakhs of people living in Bangalore—out of which nearly 12 lakhs belong to the majority community—not one of them has raised even a little finger against the construction of a mosque right in the heart of the city. Can it be said that the secular idea has not worked, that it is not spreading its benevolent influence all over the country? Is such a thing happening in other places? I would like to know if a temple is being built anywhere in West Pakistan, let alone temples and Gurudwaras being destroyed in the neighbouring country. When such is the situation that is obtaining in our country, why think of a Commission? Who is not protected? I want to know if there is any complaint anywhere that the profession, business or occupation of any particular minority is being obstructed by anybody in this country. Definitely not; nobody is obstructed merely on the ground of his religion or of his being the member of a minority class. That is the proud privilege with which an Indian looks up to the Constitution of his country. Sir, several people have visited our country and paid compliments for the working of the secular State. Why raise this topic at all now? Do you want what has been forgotten, what has been buried deep, to be raked up again? Do you want to sow discord once again in the country by setting up such a Commission. And what is the type of Commission that is wanted? Commission vested with necessary statu-

[Shri N. Sri Rama Reddy.]

tory powers. Sir, this is absolutely ridiculous. It is ridiculous that this should come from the Communist Party. And for what purpose? For protecting and safeguarding the rights and interests of the minorities in the country. Can it be said that the minority interests are not being protected and safeguarded? I do not think there will be a single person belonging to any minority class who would say that secure conditions are not prevailing in this country for his honourable living. The other day raising a question about the minorities in East Pakistan living with dignity and respect according to the agreement that was arrived at between the Prime Ministers of India and Pakistan, it was said that it was very difficult for the minorities to live in that country with respect and dignity and that has cast a gloom upon every one of us, Members of this House. We are sorry that such a situation is not obtaining in our neighbouring country. We felt glad and we felt proud that we have created in this country conditions for the honourable living of every human being. Human dignity is upheld in this country. What matters is the human consideration only. Nobody is discriminated against. Nobody's business is obstructed. Nobody's profession is obstructed. Such a situation is obtaining in this country and it is a great glory to this country. Except it be for mischief, except it be for creating disruption in the country, except it be to profit by such disruption, I do not see how a Resolution of this kind can be thought of at this stage of our life. We are already a mature country. We have passed all those stages of religion, caste or creed coming in the way of the enjoyment of the full rights which our Constitution has given us. It is ridiculous that a Resolution of this kind should be discussed in this House, in the year of 1961, fourteen years after our independence. Except for the fact that under the Rules of Procedure of this House it should be discussed, it does not require to be discussed. It ought to have been thrown out. It has no place here. I am sorry the hon. Mover is not present here now and probably to hide his shame he has gone out. It would have been better if the so-called Communists who are said to have no particular caste, community, religion or anything else, had been exposed by a Resolution of this kind. I know a few instances where the minorities have been protected at the cost of the lives of others in the event of some trouble or other. During the British period I would like to know how many riots were reported every day from one corner of the country or the other. After independence I know that communal riots of any significance could be counted on one's fingers, hardly five or six. In a vast country, in a vast sub-continent like India, where the minorities are sprinkled all over the country, there have been only five or six communal disturbances according to my reckoning. During the period when our country was subjugated by the Britishers, every year we had probably a dozen or two. I do not know it. I do not have the statistics. But I know for certain that communal disturbances of a major nature, that could be complained of, were only five or at the most six after our independence. Does it mean anything? If it means anything, it means that nobody feels insecure in this country. Nobody is feeling that he belongs to a minority caste or a minority religion. Everybody is safe. So, this Resolution requires to be thrown out, because it should be treated with contempt and I am sure every Member of the House, whether he belongs to the majority or the minority group or caste or whatever it is, would reject it, and would look down upon it with contempt. He will declare to the world that everybody in this country, in this great sub-continent, which is secular, is quite safe. Everybody is safe. Everybody's honour is upheld. Recently it was very unfortunate—there was a communal disturbance in Jabalpur. Everyone whether he belonged to the

majority community or the minority community, condemned it most. What does it show? It shows that we are true to our Constitution, running the State of ours on humane considerations and not on considerations of caste, creed, religion or anything like that. Therefore, I whole-heartedly oppose this Resolution and it requires to be treated with the greatest contempt in this country and by the world at large.

Thank you very much for giving me the opportunity.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, I wish the Mover of the Resolution, my friend, Mr. Bhupesh Gupta, had been present here. There would have been some zest, some excitement, some repartee while the discussion is going on. Now, though he and his Party are not here, we are discussing the Resolution. As I am fundamentally opposed to the Resolution, I will have to say a few things which, I think, Mr. Bhupesh Gupta, who sponsored the Resolution, would have contemplated. The Communist Party very well knows why, in view of certain currents of thought that were going on and in view of certain activities of communal parties, the Congress took the initiative and appointed the National Integration Committee under the chairmanship of Shrimati Indira Ghandi. Later on, the Government also took up the matter and the Prime Minister called a conference of Chief Ministers and took up the matter with all the seriousness that it required. Later on, the Government of India called a conference of all the parties and there was a conference for three days presided over by the Prime Minister of India. In it all parties were represented and it dealt with the matter in all its aspects—comprehensively and effectively. When they saw that the Congress was coming out with a very serious programme to tackle the question of minorities—linguistic minorities, religious minorities and other minorities—they thought that in the coming elections they would lose ground. People will say that the Communist Party which always shouts about these minorities has not done anything. In order to make up that deficiency, in order to fill that lacuna, in order to regain the position that the Communist Party had lost regarding this matter, my friend, Mr. Bhupesh Gupta, comes forward with a Resolution saying that there should be a Minorities Commission set up, as if he has the greatest feelings for the protection of minorities. I say that this Resolution at this stage is nothing more than an election stunt. Having that in mind, let us analyse it. I think no one in this House will dispute it that the Government is fully aware of the position that the minorities should not only have a sense of security, but they should have a sense of participation in the progress and administration of the country.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can continue after lunch. The House stands adjourned till 2·30.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI T. NALLAMUTHU RAMAMURTI) in the Chair.

SHRI AKBAR ALI KHAN: Madam Vice-Chairman, when the House rose for lunch, I have been submitting that so far as the minorities are concerned, it is not only the sense of security but the sense of participation in the national and developmental affairs and the administration which is the crucial thing, and I am glad to say that enlightened opinion in the country and the Government are fully alive to the situation. So far as the communal minorities are concerned, the question to a great extent has receded to the background. So far as the linguistic minorities are con-

[Shri Akbar Ali Khan.]

cerned, we will have to be very alert about them, and even in communities the question of Kayastha, Reddy, and so on, is there, and worst of all is the question of Brahmins today. So, let us fully appreciate that there is something wrong in our thinking, in our ways of dealing with the matter, in our method of tackling the problem in our approach to face the situation. There is something basically wrong and we have to be alert about it. We cannot remain complacent about it. So, so far as the Resolution of my absent but esteemed friend, Mr. Bhupesh Gupta, is concerned, if he desires to draw the attention of this House and the country that we should be alert, I am fully in agreement with him. But so far as the method that he has suggested is concerned, I think that it is absolutely uncalled for. I say uncalled for mainly for the reason that it always keeps this minority question alive, and whenever there is some permanent institution like that, whether Commission or anything else, people will always like to go to that Commission, to approach that Commission, to have grievances which are not genuine. So, I do not approve that we should make this question a permanent question by creating a sort of statutory institution. But I do feel that the policy or the method that the present Government of India has adopted to make the Chief Minister and the Home Minister in the States responsible for this purpose is right, and at the Centre the Home Minister and the Prime Minister have taken this burden on their shoulders and have expressed their determination to fight it out. I think that is the remedy, and that we have already adopted. So, my submission to this House will be, so far as this problem is concerned, let us not pooh-pooh it or say that there is nothing wrong. No, there is something wrong. Somehow or other it comes in on some occasion in some community. There is something wrong. We do not approach the problem naturally as citizens of India, as human beings. But we approach the problem, if you will pardon me for saying so, as a ladies' question or a gentlemen's question. That is also wrong. Let us help our sisters as far as we can, but let us not make it a problem and start a sort of two rival groups. I do submit that this Resolution need not be accepted, but the main object of this Resolution is to bring before the public that these are the matters which should be given the most serious consideration in order that our country may grow strong, in order that our country may progress, in order that our country may sit in the comity of nations with a clear mind and solve the problem in our humble way as we are doing in the Congo and other places.

With these words I oppose the resolution. I wish my friend was here so that we could have heard his reply.

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND: Madam Vice-Chairman, I am opposed to this resolution because I feel it is absolutely unnecessary, and not only is it not calculated to do any good to the minority communities but, if anything, it will do them harm by separating them from the other majority communities. In a free country anything that is calculated to give protection to a certain group separates that group from the other groups and creates in it a consciousness of separatism, and that is not in the interests of the unity of the country. What are minorities? You know, Madam, that we have the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes who are really minorities from the economic point of view. I do not think the other communities were meant by that term, Christians, Parsis, Muslims and many others who do not come under Scheduled Castes and Tribes. Even if in number they are minorities, they cannot be called economic minorities in the same sense, and educationally they cannot be called minorities. That way if we consider that they require help because they are economically backward, then there are many sections of the majority community too which

can come under that class. We have certainly to give help to people who are backward in any way, educationally or economically, and for that Government is doing all it can by giving various scholarships and by giving them opportunities to come forward. As a matter of fact when the country framed its Constitution, it gave separate electorates only for ten years and also other privileges to the minorities for the simple reason that if it were to make it a permanent feature of the Constitution, then it would make them feel not a part of the country but as some separate section of the country. Therefore, finding that this period was not adequate, we have extended that period. But there were many against us who were against that extension. The State has to keep a watchful eye, no doubt, over its machinery in seeing that the backward people, people who are economically backward or educationally backward, are not exploited. But that does not mean that all the time these people, by getting special privileges and by being treated as something separate, should be taught to be dependent, should be perhaps put in a state of mind to feel that they have always to have the crutches of State protection. The Constitution, as was already ably pointed out by another speaker, has put in so many clauses in articles 19, 20, 21, 22, and so on, all of them meant for protection of various rights. And there are specific provisions like article 29 regarding protection of interests of minorities. I think the main object of this Resolution at this time is not so much to get some help for minorities but to have some sort of cheap popularity by appeal to the people and by showing that the Opposition people alone have the interests of these backward people at heart, as if the Government is not there to look after their interests. My sister, Mrs. Kidwai, gave the example of Bengalis and Assamese in Assam—the minority language problem—and she suggested, therefore, that there could be a good solution if only a Deputy Minister exclusively for attending to the interests of minorities were to be appointed. There may be some force in that argument, that superficial solution. But if we are to examine that solution, we will find that such a Deputy Minister will not be able to look into the various problems connected with the minority interests that would be coming up. We have to ask whether, only because a person belongs to a minority community, irrespective of his educational and economic advancement, he should be able to get the advantages given to him and whether such a Deputy Minister should have to waste his time in solving these problems, for instance, seeing that appointments or admissions in schools, etc. are given to the children of this community. Therefore, after thirteen years of independence I feel the time has come when we should stop thinking in these terms. The more we think in these terms the more would we stand far away from being a united nation. I would ask those who think in terms of minorities, whether women themselves, should not be considered a minority.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: They are half in number. They are not in minority.

SHRI AKBAR 'ALI KHAN: You are in majority; we are in minority.

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND: I am glad my hon. friends have been caught in this one remark of mine. If women are in majority, why are they not in majority in this House and why should they not have got seats in the Legislatures? (*Interruption.*) If they are in majority, they should be in majority everywhere. If they are in majority, they should be in majority and if not in majority, at least on the basis of equality.

SHRI AKBAR ALI KHAN: Madam, I can tell you that we have more women in our Assemblies than is the case in the U.S.A. or the U.K.

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND: This is a very old stock argument being advanced by men who have had opportunities and more chances of going abroad and seeing things there. At present the representation to women has been reduced from 15 per cent. to almost 4 or 5 per cent. But that apart. My friends here who talk of the United States have to go into the reasons why they are in minority there. It is because they have many other vocations which they can go in for. They are not economically backward.

SHAH MOHAMAD UMAIR (Bihar): I should like to know whether the hon. lady Member is extending her support to the Resolution.

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND: I am not saying that. I am not lending my support to the Resolution. I wanted to develop my argument and point out that women who could ask for rights on the basis of their representation would have done so when the Constitution was framed. Mrs. Sarojini Naidu—I am sorry I am being driven into arguments. In any case you will appreciate that this is a good opportunity that I get.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: May I know whether women are in minority or in majority?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI T. NALLAMUTHU RAMAMURTI): Let the speaker go on.

(Interruptions.)

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND: Our friends are really feeling a little guilty and that is why they are rising again and again to take objection. Madam Vice-Chairman, may I point out that when they were asked whether they would like to have special privileges as a minority community like the Scheduled Castes and Tribes or other backward classes, Mrs. Sarojini Naidu and Margaret Cousins, through the All-India Women's Conference, gave their opinion that they would not like such protection because they believed in coming forward quickly without any artificial crutches and they would stand on their own feet?

My point therefore is this: I would like to point out to other minority communities also to follow the lead given by women and to act in the way they have done. They were given this opportunity. Mahatma Gandhi said that women were economically backward and they would not be in a position to go to legislatures and other places and, therefore, they should have representation. And it is on record that Mrs. Sarojini Naidu objected to that. She said that women would stand on their own rights and own abilities.

Madam Vice-Chairman, I would like to point out that the real help should be given more and more instead to economically backward communities. I would have appreciated if they had a special Ministry or a special committee even to watch the working of the privileges given to the economically-backward classes. Whether they come from a majority community or from a minority community, what happens today is this: There are some special provisions for certain minority communities, to help them, but we find that there are some people quite well-off coming from those communities and they do not require any help. Those who can help others are themselves receiving that help only because they come under that particular provision made in the interest of minority communities. I would, therefore, say that it should really be a sign of real backwardness if any thinker, any speaker or any mover, in our free country, were today to demand special privileges as a citizen and not trust the Government to do its duty. What does this Resolution demand and what does it amount to really? It really amounts

to not having any confidence in the governmental machinery. I would like to ask whether all the non-governmental machineries are doing their duty properly. If they had been doing their duty properly without any Commission like this being appointed by the Government, things would automatically have worked in the interest of minorities. The more we appoint governmental machineries for these things, the more it acts as curtailment of our civil liberties. That is an ordinary thing which should be remembered by everybody.

I would now like to say nothing more excepting to point out that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Committee that is working now would itself, if any special problems are taken to it, look into them. But I do not think there are so many people from the minority communities who would be really requiring special attention because of their backwardness as there would be from the majority communities. That is, the number of backward people in the majority community who require special treatment, as is given to any minority community, will be larger than the number of those who require help among the minority community. Therefore, the question is whether the majority community for its economically backward classes requires help, or the minority community, as was pointed out here. For these reasons, Madam, I not only oppose the Resolution but I feel such a Resolution brought before Parliament only serves to create a kind of lack of confidence in the majority community and a kind of hatred between community and community and, therefore, in national interests such a resolution should not be brought before the House.

Thank you.

SHAH MOHAMAD UMAIR: Madam Vice-Chairman, I will not embarrass you, nor will I embarrass the House with a long speech, because my voice is not co-operating with me. I was simply tempted, by the subject-matter which is under discussion today, to speak a few words.

I am sorry that the mover of the Resolution is not present. It seems that just he has planted a dynamite to disturb the Government, to disturb the minds of the people in general and of the minorities in particular and he is watching from a safe distance the action of the dynamite which he has placed over here.

This is a thing which should be very seriously taken into consideration and it should be seen whether this is the opportune time for bringing forward such a sort of Resolution just to disturb the minds of the people. There are some bad doctors who, just to earn money, put their fingers on the pulse of healthy persons and tell them that, according to their diagnosis, they suffer from a serious disease, such as T.B., and immediately advise them to go for a detailed examination of various things, of urine, blood, this and that, and to have an X-ray taken out. Many alleged T.B. patients today are victims of such money-grabbing doctors, though really there are no signs in them to reveal T.B. And after some time, when they show themselves to some good doctors, they find themselves all right, in their opinion and in actual fact, and it is because of such bad doctors that this sort of imaginary disease is noticed in healthy persons. It is just like a bad doctor, Sir, that my friend, Mr. Bhupesh Gupta, has prescribed the time for diagnosing the diseases of the minorities, and he is trying to shed crocodile tears in the name of the minorities, simply to show to them that he is their good friend and their great doctor who can alleviate all their sufferings and cure all their diseases. My friend Mr. Bhupesh Gupta should know that we are living in the sputnik and atomic age, where the sputniks and atoms—which can play havoc or can make for immense progress depending on the uses to which they are put—have

[Shah Mohamad Umair.]

become a wonder throughout the world, and where some of even the common people have, with the advance of such science and technology, progressed by leaps and bounds, and they understand what is what, and what thing has come before them with what purpose. Let me tell my friend, Mr. Bhupesh Gupta, that he should not treat the minorities as chattel to serve his own purpose, the purpose of his Communist Party.

I personally feel—that is of course a different argument—that there are no minorities in independent India. I personally regret that this conception of minority communities should be going on for so long a period. It was going on because of a lack of effort on our own part; we did not pay heed; we did not pay the required attention for national integration for the last ten or twelve years. Had it been done, in this country, today, the word 'minority' would have been scrapped from the dictionary of English and that of Hindi. No such thing would have been found in the minds and on the lips of the people today. But it remains, because we lagged behind other countries in that regard, because we neglected the central national theory and national cause. We did not look upon national integration as the first and foremost thing. Long ago it should have been preached in the country, not only preached but also acted upon. It is the first and last letter; I think it is the *Alpha* and *Omega* of the book, and if it would have been done, certainly, I think, this word would not have been found in the dictionary of India today, and my friend, Mr. Bhupesh Gupta, would not have had the opportunity for exploiting this word in the House in the form of his Resolution which is before the House.

And what is a minority? After all, let me tell you, it is my personal conception, I personally believe, it is an article of faith with me that the country cannot go on with a conception of majority and minority. It is impossible for the various sorts of progressive developments which are going on to go still further with that conception. It is impossible for the country to progress if this conception of minorities and majorities, if this sort of thing, as this right and that right, this suffering or that suffering, will continue to linger in the minds of the people, particularly in the minds of those who are Members of Parliament. Naturally, when the country is independent, that conception which existed in the time of the Britishers—it is the Britishers who coined these words, majorities and minorities—should have no place. There are majorities and minorities. There are majorities also in other Western countries. Also in Russia I had seen the minorities. But nobody uses this word "minorities". The minorities think that they are part and parcel of the majority. Just the other day, when I was speaking in the lobby with some Muslim friends about the selection of some constituencies here and there, I told them: "My friends, you are disliking this constituency because you think that here the Muslim percentage is less. If this is your conception, then, even if you get the greatest percentage of Muslim population in certain constituencies, your defeat is sure, your success is not sure, because every success and every such sort of achievement, for it to come about, depends upon the very working of the mind of the person himself." If I think that the majority are my friends and are my brothers, that I belong to a minority and have got to depend on the majority, and if I make myself friendly, so friendly that the majority will forget that I belong to a minority, the majority will treat me as one of their own. This is the way to proceed and this is the thing for which national integration is needed. National integration has not worked as yet. I am sorry to say—the Home Minister will note it—that the method in which national integration is going to be worked out requires greater attention; that requires more effective

steps, so that the persons concerned, particularly those persons who have got such germs in their minds, they should. .....

(*Time bell rings.*)

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

Just a few minutes more, Sir. I am not accustomed to speaking in a hurry, Sir. One thing I will tell you, that if this Resolution is carried, a Resolution which is intended only to be preached for voting purposes on election grounds, if my friend, Mr. Bhupesh Gupta, thinks that the electorate is so illiterate and so ignorant and so foolish today as not to understand the real purpose of the Resolution, he is wholly mistaken. The minorities know where the shoe pinches and at the same time they know that where their needs arose the Government has done the needful, and is doing everything for the minorities. I am not one of those who flatter the Government; I am one of those who speak sometimes in strong terms against the Government, which even the Opposition may not have done, but to speak in the name of minorities giving a bad name to Government and also giving indirectly a bad name to the minorities and thereby to exploit the opportunity for election purposes, this, I will say—if it is not unparliamentary—is mean political tactics of any party which exploits the minorities for such purposes at such crucial times when the country has been passing through various sorts of currents and undercurrents.

Sir, I am only sorry that certain minorities should think in terms of Conventions. If these Conventionists think that by their Conventions, by their action, certain good will be created, they are utterly mistaken. They are injuring the cause of that minority. In the name of Conventions, in the name of Resolutions, they only create disgust and distrust in the Government. It would be too much for such Conventionists to think of a healthy solution by such action. If you call a devil, the devil will come. If you go on crying that you are suffering, you are being ill-treated, then I believe the minorities, and particularly the minority which is very fond of Conventions, will go on suffering to an unlimited degree and in an unlimited scope. The only remedy for the relief of a minority is to merge itself in the majority. They should have full confidence in the majority, full confidence in the Government, that Government which is doing everything for the minorities.

It may be that something may occur here and there. How can you say that in such a great sub-continent like India, where so many minorities live, where 222 languages are spoken, nothing will happen? Things will happen but the anxiety of this Government is always there and their blood begins to boil when any such an occurrence takes place. The Government immediately comes out with relief for such minorities and take every step to stop a recurrence of such an occurrence. I can cite one instance of the great anxiety shared by our great and revered Home Minister, Lal Bahadur Ji. I wrote a letter to him about one incident which was not an ordinary thing for the Durgah of Habib Ilahi Khwaja Nizamuddin Aulia. Sir, only three or four days were left for a Moharram Tazia procession to be taken out. It was being stopped and obstructed by the authorities because a series of latrines were under construction on that passage through which that procession had to pass. I wrote a letter to our Home Minister, Lal Bahadur Ji, and the Home Minister, for whom I have the highest reverence, immediately took step. What step did he take? He at once passed order for the removal of this series of latrines which had been constructed there, and this happened so suddenly. Then I visited the place some time later and I may tell you that the entire Muslims there were singing songs of the great-

[Shah Mohamad Umair.]

ness of the Home Minister. They were so much pleased and were so happy and it seemed that great confidence, voluntary confidence and voluntary respect had been immediately infused in them by this one single thing, by the one single step which he took. Sir, even if I had been in the place of Shri Lal Bahadur Ji, I would have thought one hundred and one times before taking such a daring step which he took keeping in view the feelings of the minorities. Without taking into consideration the enormous expense incurred on the construction of those latrines which obstructed the passage of the procession he took the decision for the removal of those latrines. The generous decision which he took is a splendid example of the way in which the minorities here are being treated.

(*Time bell rings*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is up.

SHAH MOHAMAD UMAIR: Now, my friend comes forward with this Resolution. In the first instance, I think, Sir, this Resolution should not have been moved and now that it has been moved, it should be withdrawn. I do not agree with my friend, Mr. Khan, that this Resolution should be considered by the people outside so that the country knows about it. Sir, the terms of this Resolution should not go out in the country.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is time.

SHAH MOHAMAD UMAIR: Sir, with these words I oppose the Resolution, not only oppose it but vehemently oppose it. We should depend upon the National Integration Resolution for a solution.

श्री शीलभद्र याजी : उपसभापति महोदय, एक सच्चा समाजवादी होने के नाते मैं कामरेड भूपेश गुप्त के प्रस्ताव की सख्त मुखालिफ़त करता हूं । ज्यों ज्यों इलेक्शन का समय नज़दीक आता जाता है त्यों त्यों इस हाउस में कामरेड भूपेश गुप्त द्वारा इलेक्शन स्टण्ट की स्पीचेज बढ़ती ही चली जाती हैं और यह प्रस्ताव भी उसी का एक अंग है । जिस पार्टी ने टू-नेशन थीरी का नारा लगा कर देश का सत्यानाश किया और उनकी पार्टी में जितने मुसलमान थे उनको मुस्लिम लीग में भेज कर हिन्दुस्तान की ईंट से ईंट बजवाई, वही पार्टी आज इस समय में इस तरह का प्रस्ताव ला रही है ताकि इलैक्शन के समय वह माइनौरिटीज वालों से कह सकें कि हमारी पार्टी ने तुम्हारे लिये इस तरह का प्रस्ताव रखा था । इस तरह का प्रस्ताव ला कर कम्युनिस्ट पार्टी के लिये आइन्दा जो इलैक्शन आ रहे हैं उसमें घड़ियाल के आंसू बहाने के लिये और छाती पीटने के सिवाय कुछ नहीं है । वे इस प्रस्ताव द्वारा माइनौरिटीज के प्रति खैरख्वाही दिखाना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि हम माइनौरिटीज की भलाई करने वाले हैं । कामरेड भूपेश गुप्त के लिये उचित यह था कि उन्हें हाउस में रहना चाहिये था, लेकिन एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार वे पी० एस० पी०, को अपने साथ ले आये और हाउस में उन्होंने सवेरे इस तरह का तमाशा किया । क्योंकि आज रूस के प्रेसिडेंट आने वाले हैं और उन्हें वहां जाना था, इसलिये उन्होंने सवेरे ही इस तरह का तमाशा करके अपने को अलग कर लिया । उन्हें यह मालूम था कि उनके प्रस्ताव का क्या होने वाला है, इसलिये उन्होंने सवेरे इस तरह का तमाशा किया और अपने साथ पी० एस० पी० को भी ले लिया ।

SHRI JOSEPH MATHEN (Kerala): Do you know where he has gone?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order. It has no relevance.

श्री शीलभद्र याजी : क्योंकि उनको जाना था, इसलिये उन्होंने इस तरह का बहाना ढूंढा । जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि हमारे देश ने समाजवाद स्थापित करने का ध्येय अपना लिया है, इसलिये माइनौरिटीज द्वारा लिंग्विस्टिक या रिलिजस मांग करना उचित मालूम नहीं देता है । सोवियत रूस में भी कई तरह की माइनौरिटीज रहती हैं, लेकिन वहां पर इस तरह की बातें नहीं की जाती हैं जिस तरह आज कामरेड भूपेश गुप्त अपने प्रस्ताव द्वारा कह रहे हैं । हमारे देश में भी हिन्दू, सिख, मुसलमान, पारसी, ईसाई और बौद्ध तथा अनेक जाति के लोग रहते हैं और यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश की सरकार ने यह घोषित कर दिया है कि इस देश में एक समाजवादी समाज की स्थापना की जायेगी, यह एक सिक्यूलर देश होगा । जब इस तरह की घोषणा की जा चुकी है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार कोशिश कर रही है तो फिर इस तरह की बातों की गुंजाइश नहीं रहती है । यह एक बदकिस्मती की बात है कि समय-समय पर हमारे देश में साम्प्रदायिक और जात-पांत की बात कही जाती है । यह अंग्रेजों की देन है । जब अंग्रेज यहां पर थे तो उनकी नीति "डिवाइड एण्ड रूल" की थी । वे मुसलमानों और हिन्दुओं को लड़ा कर इस देश में राज्य करना चाहते थे । उन्होंने इस तरह की नीति को चलाया और उसी के द्वारा इस देश में शासन किया । उसी नीति को आधार बना कर हमारे कामरेड श्री भूपेश गुप्त इस प्रस्ताव को लाये हैं और फिर से इस नीति को जिन्दा करना चाहते हैं । इसी नीति को सामने रख कर आज उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव उपस्थित किया है । यह हमारी बदकिस्मती है कि हमारे देश में साम्प्रदायिक भावना फैली और इसको दूर करने के लिये गांधी जी को शहीद होना पड़ा । हमारी जो सरकार है वह इस बात के लिये हर तरह का प्रयत्न कर रही है कि देश में सब लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाये । यह बात सही है, जैसा कि हमारी बहन ने अभी कहा, कि माइनौरिटीज आर्थिक दृष्टि से इस देश में बैकवर्ड हैं । लेकिन लिंग्विस्टिक आधार पर या रिलिजस आधार पर इस तरह की बातें उठाना उचित मालूम नहीं देता है । जब हमने इस देश में समाजवाद की स्थापना का ध्येय मान लिया है तो किसी भी पार्टी को इस तरह की बातें नहीं उठानी चाहियें । लेकिन जहां तक पैदायश का उचित वितरण का सवाल है वह एक अलग बात है और इसके लिये हमारी सरकार ने देश में समाजवाद की स्थापना की घोषणा कर दी है । आर्थिक असमानता को दूर करने के लिये यह एक रामबाण औषधि है जिससे यह चीज दूर हो सकती है और इस चीज का देश में खात्मा हो सकता है । हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि इस तरह की बात को देश में नहीं जगाया जाये । देश में किसी भी सम्प्रदाय को, इस तरह की बात नहीं उठानी चाहिये । अगर इस तरह की बातें उठाई गईं तो देश में यह भावना बढ़ती ही चली जायेगी । इसलिये सब पार्टियों का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वे इस तरह की भावना जनता में न फैलायें जिस से देश में साम्प्रदायिक भावना फैले । किसी भी जाति के लोगों को यह नहीं कहना चाहिये कि मेरी जाति बड़ी है और उसकी छोटी है । यह बात कमीशन बनाने से दूर नहीं हो सकती है । अगर हमने इस तरह का कमीशन बनाया तो इससे देश को नुकसान पहुंचेगा । अगर हमें देश में नेशनल इंटिग्रेशन करना है तो हमें जाति-बिरादरी की भावना को बिल्कुल खत्म करना होगा और सब पार्टीज को इसके लिये मिल कर काम करना होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का, जो कामरेड भूपेश गुप्त ने पेश किया है, विरोध करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यह एक

[श्री शीलभद्र याजी]

मिसचिविस प्रस्ताव है जिससे देश में दुर्भावना फैलेगी। इस प्रस्ताव से देश में एक नई भावना फैल जायेगी और तरह तरह की माइनौरिटीज देश में पैदा हो जायेंगी और उन्हें तरह तरह की रियायतें मांगने का मौका मिल जायेगा। इसलिये जो कोई भी सच्चा समाजवादी होगा वह इस प्रस्ताव का सख्त मुखालिफत करेगा। इसलिये जैसा मैंने शुरू में कहा एक सच्चा समाजवादी और सैक्युलर व्यक्ति होने के नाते मैं इस प्रस्ताव का सख्त विरोध करता हूं।

KUMARI SHANTA VASISHT (Delhi): Mr. Deputy Chairman, I also agree with my friend Mr. Yajee that this may be more a Resolution brought forward with an eye on the coming elections or with a desire to get the sympathy of the minorities for the Communist Party. I do not think that ordinarily he came out with such strong sentiments for the minorities generally or in their party behaviour as such. I oppose this Resolution because I do not think that a Commission will really serve the purpose or be of any great help to the minorities as such but I do feel that only the Home Ministry itself can give the protection and the security that the minorities need and should have. I think all of us owe a great responsibility and duty towards the minority communities in the whole of India and it is very necessary that all efforts should be made at Government level as well as public level to give the minorities a sense of security and safety as well as fair-play. They must not feel that they are at the mercy of the majority community as they often do and they must not feel that they are not given equal opportunities with everybody. Though equal opportunities and so on have been guaranteed under the Constitution, though we may have various rights and privileges under the law, we may not sometimes have them in actual practice.

I do appreciate personally some of those fears of the minorities, particularly in Delhi. Some of the communal parties behave in Delhi—or even in Northern India—in a way that sometimes they are frightened by certain other communal parties. They hold 'Shakhas'. They are frightened by them and capital is made out of it and a lot of propaganda is made against certain communities by interested parties. That poses a very serious problem before the country, especially this wave is very strong in some places in Northern India. South India has its own different types of problems about which, of course, I am not particularly familiar, or intimately in close touch with what happens there and how the parties or groups or sects function there. About them I do not know at all but about Northern India I do realise and feel very strongly that a lot of mischief is done by them and can be done—actually it is being done now. It frightens the minorities because they feel that this particular party or communal party can damage them tremendously and they feel terribly frightened also. Somtimes they create certain incidents etc. whereby the minority community would get a good deal of blame for misbehaviour, etc. so that the feelings of the majority community can be mobilised against the minority community on the pretext of one or two incidents and a lot of propaganda can be created. A feeling would be created among the public that the Government is not maintaining law and order or cannot maintain law and order and they are the champions of the Hindu community and say that here are the minority communities who are doing a lot of injustice and so on. Unfortunately, so far as the troubles that took place recently are concerned, beginning with Aligarh and going on to the other parts of U.P., the people living there, the common man does not know that it is the majority community that has done a tremendous amount of injustice. I am very sorry to say that and I am very ashamed

to say that the majority community instead of helping and safeguarding the interests of the minorities—they have not done that at all—have really given a lot of trouble to the minority community. The feeling has gone on among a section of the people in those places in U.P. whether it is Ghaziabad or Meerut or Aligarh or those places like Chandausi, that unfortunately it is the majority community, the Hindus, who have done a lot of injustice in this matter. We must rise up and act and we must realise that the majority community must take care of the minorities in India, whether they are Muslims or Christians or Parsees or anybody else. That sense must be inculcated deeply at the Government level and public level and I am glad that the Integration Committee was set up at the national level with the idea of having State branches also, also State Integration Committees or local Integration Committees, with the idea of bringing the various communities and sections together and bringing about a greater understanding and integration. This work should be gone into very thoroughly and very diligently so that on every occasion, at every opportunity, every step is taken to bring about greater feelings of unity between the various communities and various sections. If the National Integration Committee can successfully function and implement its programme successfully, I think a major work would be done in bringing the various minorities together, and in creating greater good will between the various communities and also in creating a sense of security and fair-play.

I may also congratulate the Ministry in this matter, particularly, that various District Magistrates or Collectors in U.P. took some strong action and very quick action and stopped any type of trouble that might have gone on or taken place extensively and that would have created further difficulties or prolonged the riots and troubles in those parts of U. P. It was very good on their part to have taken some quick and strong action and they put down the elements that disrupt the law and order situation in their districts. If that is done by all the District Magistrates and Home Ministers in the various States, that will also be of certain help in this matter.

Apart from that, I may bring to the notice of the Minister that in Delhi particularly we have a very bad situation in the sense of communal parties creating so many difficulties. Government parks and places are also used by the communal parties for having their so-called 'Shakhas' where they poison the minds of small children, beginning with 5 or 6 years old right up to 18 or so. They have them every morning in the parks and with some physical training programme and other programmes, I think a tremendous amount of communal propaganda is done by them. Some of the R.S.S. activities are going on which are also very very bad. To look upon them as only a cultural organisation or social organisation is not very correct because they are not a cultural or social organisation. They are definitely a political party and they should be treated as such and there are also a large number, or at least a certain number, of Government servants in the Central Government, the State Administration as well as the Corporation who participate in the activities of the R.S.S. and even hold their meetings and othe programmes are carried on even during the lunch hour when the offices close from one to two. I think our Government servants taking such active part and being the spirit behind some of these programmes is not at all good. The Government servants should remain absolutely impartial and objective and away from all political parties. If they become involved in these communal things, then when any question comes of safeguarding the interests of the minority communities or even maintaining law and

[Kumari Shanta Vasisht.]

order or even doing something or meting out justice to ordinary citizens either by the officers of the Central Government or the State Administration or the Corporation, if those officials have very strong leanings and bias for certain communal parties, they cannot do justice to the ordinary persons, which I think would be undermining the very foundation of our Government, because the Government servants ought to be fair and objective. If they lean heavily towards the Hindus, Muslims or Christians or any communal, political party, that will be very unfortunate for our country as a whole. This should be definitely discouraged and steps should be taken to put down such activities and Government servants should not take part in processions and in meetings or meetings of various political parties, whether they be of the Jan Sangh or any other party. That is not a very good thing at all.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: The Akali Dal.

KUMARI SHANTA VASISHT: As far as the Akali Dal is concerned, and as far as my personal experience goes, I think we do not have much trouble in Delhi on that score and Government servants are not involved in their activities. They are not promoting or helping the Akali Dal's activities in Delhi, although they go out of their way to help the Jan Sangh and have their communal bias, which I think is not a healthy thing for our country. In Delhi there is no acute trouble about the Akalis, though it may be a bigger problem in the Punjab. In Delhi, their political activities are there and they are different, though at one time their activities also went to a low level and they had some very poor and dirty propaganda about our Government and even about our Prime Minister. That, of course, is unhealthy. But that is about the Akali Dal as such. I do not want Government servants . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Resolution here is about a Minorities Commission, to safeguard the interests of the minorities. We are not concerned with political parties now.

KUMARI SHANTA VASISHT: Yes, Sir, and that is why I do not want to go into the question of the Akali Dal and also we do not have any experience of Government servants being biassed in that way. What I say is that Government servants not feeling the same way for all communities or even deliberately ignoring the rights of the minority communities or their complaints or grievances, is not in our interest at all and we should have an impartial and absolutely non-communal bias among all our Government servants. Then the minority communities would have much less of complaints than they otherwise would have. There is a terrific amount of affiliation of Government servants with the communal parties. Also there is a very strong anti-social force which is gathering some momentum and spreading its own propaganda in its own way, which also is not a very healthy way, and to this also some attention needs to be given by the Government. I think we should take every step to safeguard the interests of the minority communities. I have noticed that even in the giving of jobs it is evident. Though jobs do not mean everything, still when hundreds of people are to be taken in for a particular kind of work, say, teachers and others for various categories of posts, people from the minority communities also should be taken. We should specially keep ourselves vigilant and conscious of the situation and see that even in the matter of jobs and posts and so on, our minds are clear and we should take trouble to see to it that members of the minority communities are also adequately taken into these posts and so on. If we do that, I think that would also give them a feeling of a certain amount of fairness. I suggest that special instructions may be issu-

ed to the various departments asking them to see that jobs are given to the minority communities also. By and large, sometimes it is something done unconsciously. Maybe that some people consciously ignore them and keep them out, thinking that they should not be given jobs or positions or should not even be patronised, say, in respect of the giving of shops. But I think this sort of thing happens unconsciously also. People are just casual about it. They don't wish or desire to harm their interest or damage their interest. That is not done, except by a very small section which is absolutely delinquent and wrong and is anti-social and would do anything to anybody. That section is there which is very harmful to all communities. But by and large people are not very thoughtful about this matter and so, sometimes they unconsciously overlook it. If instructions are issued to the various departments in this matter and if it is brought to their notice again and again, if they are reminded that they should give jobs, posts etc. to good applicants for the various posts from these communities, it would be helpful. I think such emphasis by the Home Ministry will go a long way. Government and the people should remember that we have no choice except to take care of the minority communities. If we fail in that we fail ourselves. We will not be failing them, but we ourselves will be failing. The Government for its own greatness and reputation must give them all the facilities, help, guarantees and safeguards, so that the minority communities may live in India with safety, security and honour.

SHRI N. M. ANWAR (Madras): Mr. Deputy Chairman Shri Bhupesh Gupta, in bringing forward this Resolution about the appointment of a permanent Minorities Commission, has really provided this House with an opportunity to get to know the minorities' problem that is now facing the country. Sir, I am not one who would rather dismiss this as a political stunt of the Communist Party. Of course, in a democracy, any party will try to take advantage of any situation that might play into its hands and, shrewd as he is, Mr. Bhupesh Gupta has brought forward this Resolution at a time when it is most opportune for him to exercise the minds of the minorities. But believe me, Mr. Deputy Chairman, to say that there is no such problem is, to run away from our responsibility. I am not looking at this problem either from the point of view of the minority or from the point of view of the majority, but I am concerned with it as a citizen of India, and I look at this problem from the point of view of our country and the reputation which this country enjoys the world over. What with the lightning rapidity of our industrial progress, what with the ideals that we have set for ourselves for a secular State, we now have got to see that as far as possible we allow no room in any quarter for any minority to feel aggrieved and in that respect I must say that our country, even though we have had these fourteen years of freedom, has yet not got out of a disease of the mind, a disease of the heart, that is, communalism. It is only the wearer who knows where the shoe pinches and it is for the members of the minority community to say how they feel about the things that they experience in life today but the remedy which Mr. Bhupesh Gupta has suggested of appointing a Minorities Commission is much worse than the disease. I do not want that this Commission should be appointed in order that it can arouse the grievances of the minorities. On the contrary, I feel, Mr. Deputy Chairman, that steps must be taken in order to win over the minorities to identify themselves with the affairs of the nation in an increasing degree. At this moment I wish to take this opportunity to express our deepest debt of gratitude to the Prime Minister for having rightly appreciated the delicacies of this problem. The country today is seized of this problem and we have now ways and means devised for promot-

[Shri N. M. Anwar.]

ing emotional integration. As the ruling party, the Congress in having appointed the National Integration Committee under the Chairmanship of Mrs. Indra Gandhi has gone a long way in trying to restore the confidence of the minorities in the party. But what is much more significant is that only recently we had the National Integration Conference presided over by our Prime Minister and in which the leading lights of our country belonging to different political parties participated. That augurs well for the future of our country, for the future of our majority, for the future of our minority, but believe me, Mr. Deputy Chairman, some references were made in the course of this debate that minorities were asking for special privileges, special safeguards. Nothing of the kind.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: Nobody raised this question. The question of women minorities was only raised; not this. This question was never raised.

SHRI N. M. ANWAR: I think somebody did. Sir, it is wrong to say that any minority is asking for special privileges and special safeguards. The Constitution has provided ample guarantees and we have pinned our faith in our Constitution. We admire and adore the Constitution for its secular ideals and for the safeguards it has provided for the minorities. But the question that now remains is one of implementation of these ideals of the Constitution. The hon. lady Member a little while ago was referring to certain tendencies which she had observed in public life in and around the city of Delhi but coming as I do from the South, from the State of Madras, I must say one thing that we do not have any problems of the kind such as have been referred to here. It is not that we are having adequate representation in the Assembly or the Council or in the Cabinet over there but what is most important is the goodwill that the minorities are enjoying at the hands of the majority community and that we have in very good measure all over the South. It is only when we come to the North that we hear stories and sometimes also incidents such as those as happened at Jabalpur and also elsewhere. But, Sir, I am conscious of one thing that while such incidents are few and far between, what we have really got to think of at the moment is the peace and goodwill that prevail all over the 600,000 villages of India. You go to any nook and corner of the country and you will find that we have carried the ideals of secularism all over and the communities are living in perfect peace everywhere. That I believe is a matter which we have got to acknowledge with gratitude and particularly as a member belonging to the minority community I feel I am never tried of saying this that it is the goodwill of the majority that is most important and that is the paramount need of our community. In that respect I must say, Mr. Deputy Chairman, that what we want is not the rule of law but the rule of love, the rule of goodwill and it is that which is going to ensure for the minorities their future in this country. I may tell you—probably it may be revealing to so many of our hon. Members in this House—that there are very many difficulties, there are very many miserable disabilities from which certain members of my community have suffered in recent years but nevertheless they have not thought of abandoning this country or getting out of the country. On the contrary, I have to say that we must be beholden to them for their dogged tenacity for their perseverance to put up with all these difficulties and live with honour in this country. That is the finest proof of patriotism that any community can demonstrate. It is easy for the majority community to preach ideals of goodwill but it is most difficult for the minority to live in a place where still they have got a certain risk to their own person and property. I must in this connection pay my meed of tribute to the Home Ministry, particularly the hon. Shri Lal Bahadur Shastri, that right from

the time he assumed charge he has dealt with many a difficult situation and with that Act for preventive detention of elements that provoke communal disorders, I now feel that we can look forward to a period of peace and security for the minorities in our country. Sir, when I have been travelling through many countries overseas I have always been feeling proud to say this that we Muslims everywhere in India—and we are not just a few but fifty millions in this country—feel not only secure but in spite of the propaganda that has been carried on particularly in so many Muslim countries—there happens to be 30 or 35 Muslim countries in the world today—I always have had the greatest pleasure to say that we in India are feeling absolutely secure. Sir, it is possible that, close as we are to the events of the partition and to the tragedy that followed, many people still harbour memories—and naturally too; I could quite imagine that and I concede it is a question of time because time is a great healer—and there are many problems which confront the minority community but I must have to admire the minority community for their courage, for their confidence, for their faith in the future of this country and but for that I am sure frustration would have set in and Members like Mr. Bhupesh Gupta would certainly have taken advantage of that situation and would have exploited it for purposes of party advantage. Sir, we have got in the South, particularly in the city of Madras, certain very healthy conventions which provide for and promote communal harmony. For election to the mayoralty of the city of Madras we have got there a communal roster and by turns the communities have the right to get elected. If the Mayor of the city of Madras happens to be for one year a Brahmin, next year there will be a non-Brahmin, for the third year a Muslim, then a non-Brahmin for another year, then a Christian and then a Harijan. That convention is being honoured for over a generation now. So it is not so much the administration of justice that counts but the manner in which it is administered that counts, that carries conviction with the minorities. We do not have any representatives in the Madras Ministry; nevertheless why is it that the Muslims in the State of Madras feel happy? It all depends upon the manner in which the majority community has carried on with the minority community. Here in North India I am very sorry to hear that there are certain movements, certain political parties, out for the very extermination of the Muslim community. It is in contrast with such parties that we have got to feel beholden to the Congress Party for having pursued the ideals of secularism and for having tried to face all odds and preserved law and order in this country. The manner in which the Home Ministry has conducted itself in trying to nip the mischief in the bud in many places where communal violence was about to break out, I must say, speaks volumes for the goodwill and for the popularity of this Government. I am sure that the intention that Mr. Bhupesh Gupta may have in mind in bringing forward this Resolution here is probably to win over the Muslim community to his Communist Party but I am absolutely confident that the minority community throughout the length and breadth of the country will stand solidly by the Congress Party because particularly the behaviour of our Government in recent months in trying to nip the mischief in the bud in places where communalism raised its head and to protect the person and property of the minorities entiles itself to the confidence, to the goodwill, to the love of the minorities. Therefore while I am not one with Mr. Bhupesh Gupta in asking the Government for the appointment of a Minorities Commission, nevertheless I can share with him his anxiety for the future of the minorities in our country. A civilised society is judged by the acid test of how it is treating its own minorities. After all, the strength of a chain depends on the weakest link and even so it is for the minority communities to give a certificate of good conduct to the majority in a

[Shri N. M. Anwar.]

democracy and it behoves a good Government that not only they should have a lot of paraphernalia of Parliamentary machinery of Government but also infuse that machinery with the flesh and blood of love and goodwill for the minorities. The world will judge us and before the bar of world opinion we will look high and erect by the manner in which we carry the confidence of the minorities. It is not so much for the mere interests of the minorities or for the goodwill of the majority, but it is for the reputation of our country as a whole. Our country which is being looked to for leadership in a thousand ways all over the world in matters of peace and in matters of international goodwill, must first set its own house in order. Here we should not give any room, any occasion, for any grievances of the kind to which Mr. Bhupesh Gupta has referred in his speech while moving his Resolution. Therefore, Mr. Deputy Chairman, I am very happy that we have had this opportunity to give expression to our views with regard to the lot of the minorities in our country. But the community to which I have the honour to belong has got tremendous faith in the ruling party, particularly because of the recent measures they have taken in order to evolve emotional integration under the auspices of the National Integration Conference and also because of the many remedial measures which the Home Ministry had taken by sanction from Parliament in trying to take into preventive custody mischief makers who are responsible for bringing a bad name to our country.

श्री नवाबसिंह चौहान (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, इस सदन में जो संकल्प श्री भूपेश गुप्त की तरफ़ से पेश किया गया है। वह ऊपर से ऐसा मालूम पड़ता है कि उससे कोई नुक़सान होने वाला नहीं है, बड़ा इनोसेण्ट है. किन्तु जब अन्दर से देखा जाये, तो उसमें एक विष का भंडार दिखाई पड़ता है । वह विष जो भारत को विभिन्न कालों में टुकड़े-टुकड़े करता रहा है और जिसने हमारे राष्ट्र के टुकड़े-टुकड़े करके तहस नहस कर दिया, उसको आज फिर इस प्रस्ताव के रूप में हमारे मित्र ने सदन के सामने रखा है । शायद हमारे मित्र का मन्तव्य इस प्रस्ताव को रखने का यह है कि जल्दी ही जो चुनाव सारे देश में होने वाले हैं, उसमें फ़ायदा उठाया जाये, लेकिन मैं इससे भी आगे बढ़ना चाहता हूं । दो महीने बाद चुनाव खत्म हो जायेंगे और पांच वर्ष बाद फिर आयेंगे । लेकिन वे इस प्रस्ताव द्वारा एक स्थायी कमीशन बनाना चाहते हैं । उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है और जो अधिकार इस कमीशन को वे प्रस्ताव द्वारा दिलाना चाहते हैं, वह बात बहुत ही गम्भीर है । अगर इस तरह का कमीशन इस देश में स्थापित हो जायेगा, तो सब जाति के लोग यह समझने लगेंगे कि अल्पमत होना बड़े फ़ायदे की चीज है । इसमें शामिल होने से हमारे बच्चों को वज़ीफ़े मिल जायेंगे और सरकारी नौकरी भी आसानी से मिल जायेगी । इसका नतीजा यह होगा कि हिन्दुस्तान में कोई भी ऐसी जाति नहीं रह जायेगी, जो माइनौरिटी बनने के लिए तैयार न हो । आप लोगों ने अभी हाल में अखबार में पढ़ा होगा कि मैसूर स्टेट में जब बैकवर्ड क्लासेज़ के लोगों को सहूलियत मिलने के बारे में खबर निकली, तो तमाम जातियों के लोग अपनी जाति को बैकवर्ड जाति में लिखाने लगे । अगर सरकार इस कमीशन की बात को मान लेती है, तो इसका नतीजा यह होगा कि बहुत से लोग अपनी जाति से अलग हो कर माइनोरिटी में अपना नाम मुस्तकिल तौर पर लिखाने लगेंगे । मुसलमान जाति में भी बहुत सी जातियां हैं और इसी तरह से हिन्दू जाति में भी बहुत-सी जातियां है । अगर हम प्रस्तावक-महोदय की बात को स्वीकार करते हैं, तो यह सभी जातियां भी अपने को माइनौरिटी में कहलाना चाहेंगी, ताकि उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा सहूलियत प्राप्त हो सके । साथ ही साथ यह होगा कि यहां से कुछ आदमी किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वे वहां पर

माइनौरिटी पर हो जायेंगे । वह दूसरी जगह से यहां आ कर अल्पमत में हो जायेंगे । जब हम सारे देश में इस समय एकता और देश की अखंडता पर ज़ोर दे रहे हैं, तो इस तरह के प्रस्ताव को मान लेने से हमारे सारे प्रयासों पर पानी फिर जायेगा । जब भी हमने इस तरह की बातों को माना, तब तब हमारे देश के टुकड़े-टुकड़े हो गये । इसलिए हमें इस तरह की भावना देश में फैलानी चाहिये, जिससे हमारा राष्ट्र एक सूत्र में बंध सके । हमारे देश की राष्ट्रीय सरकार और देश के नेता, देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जिस तरह का प्रयत्न कर रहे हैं, उसको खंडित करने के लिए हमारे कम्युनिस्ट भाई इस तरह का प्रस्ताव लाये हैं । मैं इस बात पर ज्यादा बहस करके सदन का समय नष्ट करना नहीं चाहता हूं । यह बात सब जानते हैं कि हमारे कम्युनिस्ट भाइयों का मक़सद इस देश में क्या है ? वह इस देश में कम्युनिस्ट शासन ही नहीं चाहते हैं, बल्कि वह कुछ दूसरी ही चीज़ चाहते हैं; क्योंकि उनकी जो वफ़ादारी है, वह किसी बाहरी देश के प्रति है । इसलिए इस दृष्टि को सामने रख कर अगर हम इस प्रस्ताव को देखेंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा कि यह जो प्रस्ताव रखा गया है, बहुत ही खतरनाक प्रस्ताव है । जहां तक माइनौरिटी का सवाल है इसकी परिभाषा नहीं की जा सकती है । कहीं पर स्त्रियां कहती हैं कि हम माइनौरिटी में हैं और कहीं पर मर्द कहते हैं कि हम माइनौरिटी में हैं । हमारे ज़िले में जो रिफ़्यूजी हैं, वे अपने को माइनौरिटी वाले कहते हैं । यू० पी० से जो लोग पंजाब में चले गये हैं, वे लोग अपने को माइनौरिटी वाले कहते हैं । आपको दिल्ली में भी बहुत-से लोग मिलेंगे, जो अपने को यहां माइनौरिटी में कहते हैं । इस तरह से माइनौरिटी का कोई ठिकाना नहीं है । यहां पर सवाल माइनौरिटीज़ का मानी, कम तादाद और ज्यादा तादाद का नहीं है । यहां पर तो सवाल अधिकार प्राप्त करने से है । हमारा संविधान यह बतलाता है कि एक दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करना चाहिये । हमें इंसानियत से नीचे नहीं गिरना चाहिये । अगर हम किसी को, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे हिन्दू हो या किसी धर्म का मानने वाला हो, क़त्ल कर देते हैं, तो हमको यह समझना चाहिये कि हम इंसानियत से नीचे गिर गये हैं । अगर हम किसी को नुक़सान पहुंचाते हैं, तो हम एक तरह से उसका अधिकार छीन लेते हैं । इस दृष्टिकोण को सामने रख कर अगर हम चलेंगे, तब हमारा उद्धार हो सकता है । अगर हम स्वयं ही नई नई माइनौरिटी पैदा करेंगे, तो देश में एकता पैदा नहीं हो सकती है । जब लोगों को यह मालूम हो जायेगा कि माइनौरिटी की सूची में नाम लिखाने से तरह तरह के अधिकार मिलते हैं, तो मैंने पहले कहा है, सब लोग अपनी जाति को लेकर माइनौरिटी की लिस्ट में अपना नाम, अधिकार प्राप्त करने के लिए लिखवायेंगे । जब आप इस प्रकार मेजोरिटी-माइनौरिटी की बात करते हैं, तो यह विचार नहीं करते कि जो एक प्रकार माइनौरिटीज़ में हैं, वह दूसरे प्रकार से मेजोरिटी में हो सकते हैं । इस तरह से धार्मिक दृष्टिकोण, भाषायी दृष्टिकोण और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी माइनौरिटीज़ व मेजोरिटीज़ हो सकती हैं, और इन कम्युनिस्टों का उद्देश्य तो सदैव राजनीतिक ही होता है । माइनौरिटी-मेजोरिटी का बखान करने में । श्री भूपेश गुप्त, जो प्रस्ताव लाये हैं, उसका अर्थ यह होगा कि कुछ लोग अपनी जनसंख्या के हिसाब से तो मेजोरिटी में होंगे, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से वे अपने को माइनौरिटी में गिनेंगे और कहेंगे कि हमारे पास तो धन नहीं है । अतः हम आर्थिक माइनौरिटी हैं । जैसे कलकत्ते में मारवाड़ियों की संख्या कम है, लेकिन कारोबार ज्यादा उनके ही पास है । इस तरह से यह मेजोरिटी और माइनौरिटी की जो डैफ़िनिशन है, उससे जो माइनौरिटी में है, वह मेजोरिटी वाला कहलाया जायेगा और जो मेजोरिटी में है, वह माइनौरिटी में कहलाया जायेगा । इसके बारे में फ़ैसला करना बहुत मुश्किल हो

[श्री नवाबसिंह चौहान]

जायेगा और यह निर्णय लेने से पहले कि यह माइनौरिटी में है या मेजोरिटी में है, उसके पीछे की हिस्ट्री में भी जाना पड़ेगा। इस तरह से यह जातीयता का बखेड़ा बढ़ता ही चला जायेगा कि कौन कहां से आया है और कौन किस बिरादरी का है। इस तरह से देश के अन्दर अनेक साम्प्रदायिक तत्व उठ खड़े होंगे और देश में फूट पैदा हो जायेगी। इस प्रस्ताव में जो कमीशन की बात कही गई है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे कम्युनिस्ट मित्र संभवतः यह समझते हैं कि गवर्नमेंट शायद इस तरफ़ नहीं देख रही है और वह माइनौरिटी की कतई परवाह नहीं कर रही है। जब गवर्नमेंट परवाह नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट का पैदा किया हुआ और बनाया हुआ यह कमीशन कैसे परवाह करेगा ? यह सोचने की बात है। साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी इसे समझ सकता है। जब आपको सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है, तो उसी सरकार का नियुक्त किया हुआ या बनाया हुआ एक कमीशन कैसे इन समस्याओं को हल कर लेगा। यह एक ऐसा विरोधाभास है कि इसके समझने के लिए यदि हम ज़रा भी विवेक से काम लें, तो इनके तमाम तर्कों का और मन्तव्यों का पर्दा फ़ाश हो जाता है। इसलिए वे फ़जल की बात कहते हैं। जिस पार्टी से वे सम्बन्ध रखते हैं, उसको मैं चुनौती देता हूं कि जब से कांग्रेस सरकार बनी है, तब से ही नहीं बल्कि उससे पहले का जो हमारा इतिहास है, जबकि हम अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे थे और जेलखानों में जाते थे, तब भी हमारे बहुत-से नेता इसके लिए प्रयत्नशील थे और गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने तो अपने प्राणों की आहुति ही दे दी थी और महात्मा गांधी ने अनशन किये थे। जो अस्पृश्य कहे जाते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से अपने को माइनौरिटी समझते हैं, उनके अधिकारों को बचाने के लिए और उनको हर तरह से ऊपर उठाने के लिए पहले से ही प्रयत्न शुरू हो गये थे। जिन चीज़ों से हमारे देश का विनाश हुआ था, उनकी तरफ़ हमारे नेताओं ने पहले देख लिया था और उनमें सुधार करने का वे बराबर प्रयत्न करते रहे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने इस सम्बन्ध में क्या प्रयत्न किये, सिवाय इसके कि अपने प्रोपेगेंडा के लिए यहां आ करके या कहीं बाहर प्लेटफ़ार्म से वे ऐसी बातें कहते रहे और लोगों को बरगलाते रहे। जब देश का बटवारा हुआ तो वह इस तरह से हुआ कि जो अंग्रेज़ इम्पीरियलिस्ट थे, साम्राज्यवादी थे, उन्होंने माइनौरिटीज़ को बरगलाया। यही नहीं है कि सिर्फ़ मेजौरिटी के लोग ही शरारत कर सकते हैं, बल्कि माइनौरिटी के लोगों से भी शरारत करवाई जा सकती है। हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए कांग्रेस की तरफ़ से पता नहीं कितने प्रयत्न किये गये। यदि उधर से ४० फ़ी सदी की मांग की गई और इधर से ५० फ़ी सदी भी देने को तैयार हुए फिर भी अंग्रेज़ों ने अपनी चाल से हिन्दू-मुसलमानों को आपस में मिलने नहीं दिया, क्योंकि उनकी "डिवाइड एंड रूल" की नीति ही थी। हमारे कम्युनिस्ट मित्रों की भी वही नीति है कि देश में तफ़रक़े बढ़ें, लड़ाई होती रहे, ताकि उनकी पूछ होती रहे और वे लोगों को बहका करके इलेक्शन में जीत करके यहां आ सकें। तो इनकी वही नीति है, जिस नीति ने देश में खून बहाया। आज भी दूसरी तरफ़ पाकिस्तान के हिस्से में देखिये कि वे क्या कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जो कुछ वहां होता है उसी के प्रतिक्रियास्वरूप इस देश में भी बहुत-सी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन वह शरारत करने वाले मेजोरिटी नहीं होते हैं। चाहे जिस भी कम्युनिटी को आप ले लीजिये, यहां हर कम्युनिटी में मेजोरिटी शरारत करना पसन्द नहीं करती। कुछ थोड़े से ही शरारती, ग़लत काम करने वाले और मानवाधिकारों की इज्ज़त न करने वाले ऐसे लोग हैं, जो इस तरीक़े के बुरे काम करते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों को, इस आधार पर नहीं देखना चाहिये और साथ ही साथ हमें यह कोशिश करनी चाहिये कि हम ठीक ढंग से,

रेशनल ढंग से, इन चीज़ों को सुलझायें । अगर श्री गुप्त के बताये गये आधार पर हम इन चीज़ों को सुलझाने लगेंगे, तो बड़ा गड़बड़ हो जायेगा । हम अपने पुराने इतिहास पर भी यदि दृष्टि डालते हैं, तो हम यह पाते हैं कि पिछले ज़माने में जब अंग्रेज़ यहां राज्य करते थे, तो वे भी माइनौरिटी में थे और उनसे पहले जब मुसलमान यहां राज्य करते थे, तो वे भी माइनौरिटी में थे । किन्तु अब जब प्रजातंत्र स्थापित हो गया है, तो प्रजा का राज है । आप यह कह सकते हैं कि शासन में एक धर्मावलम्बी लोग अधिक आ गये हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते हैं कि यह कोई किसी विशेष मत की मेजौरिटी का राज है । आज जो यह मेजौरिटी बनी हुई है, यह बहुत से लोगों से मिल कर बनी हुई है । यह मुसलमानों से भी मिल कर बनी हुई है, यह ईसाइयों से भी मिल कर बनी हुई है, जो परिगणित जाति के लोग कहे जाते हैं, उनसे भी मिल कर बनी हुई है और मुझे इस बात के कहने में फख्र है कि इसमें सबके नुमाइन्दे मौजूद हैं । मुसलमानों के लिए सीटें अलग निश्चित नहीं की गई हैं । लेकिन हमारे यहां पार्टी के आधार पर हमेशा यह कोशिश की जाती है कि हम अधिक से अधिक मुसलमान भाइयों को यहां लावें । इसके साथ साथ आपने यह भी देखा होगा कि हिन्दू बहुमत वाले स्थानों पर चाहे हिन्दू हार गये हों, लेकिन कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए मुसलमान नहीं हारे हैं और अधिक संख्या में वे यहां मौजूद हैं ।

इसी तरीक़े से हमारी बहनें कहती हैं कि हम भी माइनौरिटी में हैं । लेकिन यह माइनौरिटी ऐसे ज़ोर की है कि इसके सामने सब के सिर झुक जाते हैं और इनको लाने की भी हम पूरी कोशिश करते हैं ।

अब आप यह देखिये कि हमारे कम्युनिस्ट भाई क्या करते हैं । हम यह देखते रहते हैं कि ये देहातों में क्या हरकतें करते हैं । वहां ये जाति बिरादरी का नारा लगाते हैं और जाति बिरादरी के आधार पर अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं और फिर यहां आकर के इस तरह से बातें करते हैं । वे ऐसी सारी बातें केवल इलैक्शन जीतने के लिए करते हैं । लेकिन हम चाहे हार जायें, हमारी गवर्नमेंट चाहे न बने, लेकिन जो हमारे सिद्धान्त हैं, उनको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं । इसलिए मुझे आशा है कि इस तरह का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जायेगा, क्योंकि इस आधार पर हिन्दुस्तान में कोई मेजोरिटी या माइनौरिटी नहीं है । आज जिसे मेजोरिटी कहा जाता है वह एक मुस्तक़िल चीज़ नहीं है । मैं आज अगर जीत जाता हूं तो मेरी मेजोरिटी बन जाती है और मेरे मुकाबिले में जो हार जाता है उसकी माइनौरिटी बन जाती है । लेकिन पांच साल के बाद अगर मैं हार जाऊं, तो मेरी माइनौरिटी बन जायेगी और जो जीतेगा, उसकी मेजौरिटी बन जायेगी । इस तरह मेजोरिटी और माइनौरिटी का सवाल ही नहीं उठता ।

इसलिए मैं यह समझता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत ज़हरीला प्रस्ताव है और हमारे बुज़ुर्ग शाह मुहम्मद उमेर ने जो भावना प्रगट की, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

ज्ञानी जैल सिंह (पंजाब) : उपसभापति महोदय, बदक़िस्मती से जो लोग इस प्रस्ताव की हिमायत करते थे, वे मौजूद नहीं हैं । इस सिलसिले में बहुत सी तक़रीरें हो चुकी हैं और बहुत से ख़यालात का इज़हार हो चुका है, जिनको दोहराना मैं ज़रूरी नहीं समझता । मगर खुद माइनौरिटी का एक मेम्बर होने की हैसियत से मैं यह अपनी ड्यूटी समझता हूं कि ऐसी बात जो हमारे सामने आती है और उसके मुतल्लिक़ हम क्या राय रखते हैं, उसको मैं यहां

[ज्ञानी जैल सिंह]

पेश कर दूं । मैं इस बात से इत्तिफ़ाक़ करता हूं कि आज़ादी के बाद चौदह साल के अन्दर हम हिन्दुस्तान में जो एकता की भावना लाना चाहते थे, वह नहीं ला सके । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि देश में बहुत सी फ़िरक़ावाराना ताक़तें क़ायम हैं और न सिर्फ़ माइनौरिटी में हैं, बल्कि मेजौरिटी में भी हैं । जब हम देखते हैं कि ८५ फ़ी सदी हिन्दू जाति के लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं कि हमको ख़तरा है, तो इस बात से हमें बहुत आश्चर्य होता है और जब वे कहते हैं कि ख़तरा है, तो माइनौरिटी वाले भी कहते हैं कि ख़तरा है । अगर देखा जाय तो दरहक़ीक़त कोई ख़तरा नहीं है, न माइनौरिटी को ख़तरा है और न मैजौरिटी को ख़तरा है । बात सिर्फ यह है कि लोग सस्ती लीडरशिप चाहते हैं और लोगों के जज़्बात को भड़का कर वे जज़्बात से खेलना चाहते हैं । दरहक़ीक़त न हिन्दुस्तान में ऐसे कमीशन की ज़रूरत है और न ऐसी किसी कमेटी की ज़रूरत है । ज़रूरत तो सिर्फ एक ही बात की है कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कांस्टिट्यूशन है उसके मुताबिक़ पूरे तौर पर अमल किया जाये । भारत सरकार ने

4 P. M. जो इंसान के बुनियादी हक़ूक़ हैं उसके लिये मुकम्मल अमल करने का यत्न किया है और यह हिन्दुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिस में कि इतने फ़िरकेवाराना झगड़े होते हुए भी हिन्दुस्तान की माइनौरिटीज़ को कोई किसी क़िस्म की शिकायत नहीं है । मैं यह मान सकता हूं कि लोग अपनी लीडरशिप बनाने के लिये तरह तरह की बातें करें मगर जब वह हिसाब-किताब पर आते हैं तो वे इस बात में फेल हो जाते हैं उनके पास कोई सबूत नहीं होता है । आज थोड़े दिनों की बात है कि पंजाब में अकाली दल ने इस बात की शिकायत की कि सिखों के साथ भेद-भाव वाला सलूक होता है और डिस्क्रिमिनेशन होता है । इस पर हमारे प्रधान मंत्री ने एलान किया कि हम एक कमीशन मुक़र्रर करते हैं और वह कमीशन भी मुक़र्रर किया गया । जब कमीशन मुक़र्रर हो गया और उसने काम शुरू किया तो वह पार्टी और उसके लीडर भाग गये और उन्होंने अपना कोई मामला उसके सामने नहीं रखा । मैं समझता हूं कि भागने के सिवाय उनके लिये और कोई चारा ही नहीं था । क्योंकि कोई सवाल ही नहीं था जो कि उनके सामने रखा जाता । बहाना बनाया गया कि उसमें हमारी इच्छा के मेम्बर नहीं लिये गये । अपना यह हक़ सरकार कैसे छोड़ सकती है । बहुत ऊंची सतह के जुडीशियल-माइंडेड आदमी उस कमीशन में मुक़र्रर हुए मगर उस कमीशन की यह हालत है कि उस के पास कोई केस ही नहीं आता है । तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की दूसरी जो और माइनौरिटीज़ कही जाती हैं, उनके पास भी कोई ऐसी ही शिकायत नहीं है, ऐसा सबूत नहीं है, जिनके लिये कोई कमीशन मुक़र्रर किया जाये ।

मुझे इस बात से हैरानी होती है कि जिस पार्टी का स्टैंड आर्थिक बुनियादों पर है, जो कि एकतसादी प्रोग्राम को ले कर के चलना चाहती है, उनको इस बात का ख़याल कैसे आ गया कि हिन्दुस्तान की जो माइनौरिटीज़ हैं, उनके हक़ूक़ की हिफ़ाज़त की जाये ? मैं तो यह समझता हूं जैसा कि ऑनरेबिल मेम्बर साहबान ने यहां अपना ख़याल प्रकट किया है कि यह उनका कोई इलेक्शन स्टेंट होगा । ख़ैर, मैं इस झगड़े में नहीं जाता और न मैं उनकी नीयत पर ही यह शक करता हूं, मगर एक बात ज़रूर कहे देता हूं कि हिन्दुस्तान में इस बात की चर्चा

जितनी हम ज्यादा करते हैं उतनी ही यह बीमारी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। यह चर्चा बहुत लोग करते हैं, मैं सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ही नहीं कहता हूं, कुछ हमारे में भी ऐसे लोग हैं जो कि चर्चा करते हैं और उनके दिमाग पर फ़िरकेदारी का भूत सवार रहता है। मैं उनकी फ़िरकेदारी से ज्यादा खौफ खाता हूं जो कि छिपकर फ़िरकेदारी का बीज अपने दिमाग में रखते हैं। "नज़र में मुलाक़ात हो गई, रहे दोनों खामोश पूरी बात हो गई।" वह अपनी बात कर लेते हैं और उस बात पर चलते हैं और इस तरह फिरकेदारी को बढ़ावा देते हैं। आज हिन्दुस्तान की माइनौरिटीज़ को जिस तरह से बराबरी के हक़ूक मिल रहे हैं और जिस जिस तरह से उनको मुनासिब हक़ूक मिल रहे हैं उसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिल सकती। मगर बदकिस्मती से हिन्दुस्तान की तकसीम हुई और उस तकसीम में अफसोस की बात यह हुई कि कम्युनिस्ट पार्टी ने भी ग़लती की। उन्होंने उसकी हिमायत की और उन्होंने हिमायत किस बात की की। इस बात की कि जिन इलाकों में मुसलमानों की मैजौरिटी थी वहां मेजौरिटी के लिये कहा कि इनको राज देना चाहिये और माइनोरिटी को उनके रहम पर छोड़ दिया गया। अगर माइनोरिटी का उनको खयाल होता तो यह बात हिन्दुस्तान के बटवारे की न होती, मगर वह हो गई। अब उसके होने के बाद क्या बात चलती है? चूंकि हमारे साथ एक इस्लामी मुल्क है और उस इस्लामी मुल्क का जो कानून बनने जा रहा था जो कि बन नहीं पाया उस आईन में उन्होंने यह रखा था कि कोई गैर-मुसलमान वहां का प्रधान नहीं हो सकता, तो ऐसे देश का पड़ौस होने की वजह से जब वहां माइनोरिटी की चीख पुकार निकलती है तो उसके जवाब में, उसका जवाब देने के लिये, हिन्दुस्तान में यह चीज़ पैदा कर दी जाती है कि हिन्दुस्तान में भी माइनोरिटी को तकलीफ है। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बातें हैं। हिन्दुस्तान में माइनौरिटी के लिये कोई तकलीफ पैदा नहीं हुई और न ऐसे कमिशन की जरूरत है। अगर कमिशन बनेगा तो इस बात से माइनौरिटीज़ को नुकसान होगा। आप कहेंगे, सोचेंगे, कि कैसे होगा? मैं समझता हूं कि माइनौरिटी को नुक्सान इसलिये हो जायगा कि अभी हिन्दुस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम होने की वजह से हर एक पार्टी को यह सोचना पड़ता है कि उसके खिलाफ यह इल्जाम न आ जाय कि इसने माइनौरिटीज के साथ बेइंसाफी की है इसलिये उनके लिये कुछ रियायत करनी चाहिये। कमिशन होने पर यह बात नहीं हो सकेगी। कमिशन जो है वह हमको रियायत नहीं दिला सकती है क्योंकि आम तौर पर जो कमिशन मुकर्रर होते हैं वे जुडिशियल आदमियों के होते हैं और जुडीशियल आदमी कागज पर चलते हैं, शाहादत पर चलते हैं और वे कभी यह सोच नहीं सकते कि इनके जज़बात को हम कैसे सम्हाल सकते हैं। मैं चाहूंगा कि कम्युनिस्ट पार्टी भी ऐसी मिसाल क़ायम करे जैसी कि भारत सरकार ने, जो कि कांग्रेस की सरकार है उसने, कांग्रेस ने मिसालें कायम की हैं। पंजाब की एक रेजिडेंसी है जिसका नाम अम्बाला है, वहां मुसलमान का एक ही वोट है, उनका दूसरा वोट उस हल्के में नहीं है मगर वह तीन दफा कांग्रेस के टिकट पर मेम्बर चुने जा चुके हैं और वे बड़ी भारी मेजौरिटी से चुने जाते हैं, तमाम कम्युनल पार्टियां उनकी मुखालिफ़त भी करती हैं, जज़बात को भी भड़काती हैं मगर वह भड़का नहीं पाती हैं। तो एक नहीं बहुत सी ऐसी बातें हिन्दुस्तान में हैं जो कि हमारे सामने आ सकती हैं। मेरी नजरों में ऐसे भी लोग हैं, जैसे कि सिखों में से कोई अगर मिनिस्टर बन जाय और वह धनी बन जाय तो क्या वह गरीब सिखों का खयाल करता है, क्या वह भी यह देखता है कि वह किसान और मजदूर

[ज्ञानी जैल सिंह]

है जो कि अपने कमाई के लिये रोता है, मरता है, जिसके घर में दिया जलाने के लिये तेल भी नहीं होता है और उसके बच्चे भूखे रहते हैं। तो क्या उसके लिये कोई कुछ ज्यादा दे देता है ? मैं समझता हूं कि उसे कुछ नहीं मिलता है। तो मेरा कहना है कि अगर हम ऐसी बातें अपने दिमाग में रखेंगे और माइनौरिटी और मैजौरिटी का हिसाब किताब चलता रहेगा तो हमारा देश तरक्की की तरफ नहीं जा सकेगा।

खैर, मैं यह तो नहीं कहता कि नेशनल इंटेग्रेशन का काम हमको नहीं करना चाहिये। करना चाहिये, मगर मुझे आश्चर्य होता है कि १४ साल के बाद अब नेशन को इंटेग्रेट कर रहे हैं। नेशन तो इंटेग्रेट हुई ही है, हिन्दुस्तान की जनता इंटेग्रेटेड है और वह आपस में एकता रखती है मगर उस एकता को तोड़ने की जो कोशिश करते हैं हमें उनका मुकाबिला करना चाहिये।

जैसाकि मैंने अर्ज किया था कि ईक्वल अपौरचुनिटी देने के लिये हमारा जो आईन है उसके मुताबिक कुछ लोगों को ईक्वल अपौरचुनिटी नहीं मिलती है लेकिन वह माइनौरिटी मैजौरिटी के हिसाब से नहीं बल्कि वह तो आर्थिक तौर पर नहीं मिलती है। मेरे सामने मिसाल है। आज आप देखते हैं कि हिन्दुस्तान में एलेक्शन आता है और क्या एलेक्शनों में इक्वल अपौरचुनिटी मिलती है ? ये जो राजा महाराजा हैं, जो कि कभी रियासतों के राजा थे, महाराजा थे, उनको स्पेशल प्रिवलेजेज हैं, उनकी कारों पर झंडियां लगती हैं, वह अपना पहरा रख सकते हैं, उनके पास असलाह रहता है, उनको प्रिवी पर्स मिलती है और वे एलेक्शन लड़ सकते हैं लेकिन एक पटवारी एलेक्शन नहीं लड़ सकता है जो कि ६० या ७० रु० का मुलाजिम है। तो यह ईक्वल अपौरचुनिटी नहीं है और ऐसी बातों में हमें जरूर ध्यान देना चाहिये।

डिप्टी चेयरमैन साहब, आपके द्वारा मैं भारत सरकार से यह दरख्वास्त करूंगा कि वह इस बात पर जरूर गौर करे कि हमने आईन में जो फंडामेंटल राइट्स दिये हैं उनके बारे में कहीं किसी के साथ कोई बेइंसाफी तो नहीं होती। इसके लिये उसको जरूर जांच करनी चाहिये मगर ऐसे कमिशन हरगिज कायम नहीं करना चाहिये नहीं तो तमाम लोगों की जो इनर्जी है वह दूसरी तरफ चली जायेगी। हम तो हिन्दुस्तान की गरीबी को खत्म करना चाहते हैं। अगर हिन्दुस्तान के भूखे लोगों को हमने खाना खिला दिया, बेघरों को घर दे दिया, बिना कपड़े वालों को कपड़ा दे दिया तो फिर हिन्दुस्तान की कोई प्रौब्लम नहीं रहेगी। इसी तरफ भारत की सरकार चलती जा रही है और मैं समझता हूं कि उसको इसी तरफ चलना चाहिये। जब कभी भी हिन्दुस्तान की किसी माइनौरिटी का कोई सवाल आया तो भारत सरकार ने खुले दिल से माइनौरिटी के साथ इंसाफ ही नहीं किया बल्कि उसको वह रियायत भी दी जो कि देनी चाहिये। इसलिये मैं इस रिजोल्यूशन का विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि ऐसे रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। यह हार्मफुल हो सकता है, यह कंट्री के लिये नुकसानदेह हो सकता है और यह माइनौरिटीज के लिये भी नुकसानदेह हो सकता है।

श्री देवकीनन्दन नारायण (मुम्बई) : उपसभापति जी, मैं सोच रहा था कि इस देश में ऐसा कौन इंसान है जो कि माइनौरिटी में नहीं है क्योंकि नीचे से ऊपर तक देखियेगा, ग्राम पंचायत से शुरूआत कीजिये और पार्लियामेंट तक पहुंचिये। ग्राम पंचायतों में आपको दिखाई देगा कि एक गांव में ब्राह्मण माइनौरिटी में हैं तो राजपूत मेजौरिटी में हैं और आगे आपको पता चलेगा कि किसी गांव में कोई एक जाति मेजौरिटी में है तो कोई दूसरी माइनौरिटी में है। तो, किसी न किसी जगह माइनौरिटी में कौन नहीं है। सोचियेगा।

हिन्दुओं में इतनी असंख्य जातियां हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है। माइनौरिटीज़ और मेजोरिटीज़ हिन्दू समाज में गांव गांव में भिन्न है। आप सामाजिक माइनौरिटीज़ को ही लेंगे तो भी यह माइनौरिटीज़ का सवाल कभी मिटने वाला नहीं है कारण ये परमानेंट माइनौरिटीज़ हैं।

जहां तक रिलीजस माइनौरिटीज का सवाल है हमारे यहां इतने पंथ हैं, इतने मजहब हैं कि कोई न कोई मजहबी माइनौरिटी हो सकती है। मैं मजहबी माइनौरिटी वालों से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा मजहब है जिसको यहां हिन्दुस्तान में रहने की इजाजत नहीं है, यानी मजहब के कारण कोई दिक्कत उनके सामने पैदा हो गई है कि जिसके कारण वे अपने मजहब का पालन नहीं कर सकते। ऐसी कोई बात हो तो फिर कहा जाय कि मजहबी माइनौरिटी के साथ अन्याय हो रहा है, सो तो अभी तक किसी ने नहीं कहा है, इस सदन के अन्दर और न मैंने बाहर सुना कि मजहब के पालन में हमें कोई दिक्कत सरकार की तरफ से पैदा हो रही है। दूसरी लिंग्विस्टिक माइनौरिटी है और उसका बन्दोबस्त सरकार ने कर रखा है। लिंग्विस्टिक कमीशन है और वह लिंग्विस्टिक माइनौरिटीज जहां जहां हैं उनको पढ़ने पढ़ाने की हर वक्त कोशिश करती रहती है और इस कोशिश में कामयाब भी होती है। उनकी सालाना रिपोर्ट हमारे सामने पेश होती है।

इसके बाद हैं पोलिटिकल माइनौरिटी ये तो बदलते रहते हैं। आज एक पोलिटिकल माइनौरिटी है, कल वह मैनोरिटी हो जायगी और कल की मैजौरिटी परसों माइनौरिटी हो जायेगी। तो यह कोई एक माइनौरिटी नहीं है। और फिर आज जो इस पार्टी में हैं वे कल वहां पहुंच जायेंगे। तो इस तरह से आप किसी निगाह से देखियेगा, आपको अनगिनत अनेकानेक माइनौरिटीज मिल जायेंगी हिन्दुस्तान में, कोई छटेगा नहीं कसी न किसी माइनौरिटी से, क्योंकि पहली सबसे बड़ी माइनौरिटी तो हिन्दुओं ही की है। जैसा कि महात्मा गांधी ने उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान बना, कहा था कि यह कहना कि हिन्दू मेजोरिटी में हैं इससे बढ़कर कोई गलती नहीं हो सकती। ये महात्माजी के शब्द हैं—इससे बढ़कर कोई गलती नहीं है। हिन्दुओं में इतनी जातियां हैं और ये एक दूसरे से दुश्मनी भी रखती हैं, विरोध भी रखती हैं, खान पान तक नहीं करतीं, छुआछूत भी पालती हैं, इतने फर्क हैं उनमें कि हिन्दुओं को मेजौरिटी में कहना, यह गलतफहमी है।

आप देखिये कि सच्ची माइनौरिटी और मेजौरिटी इकनौमिक है जिसकी वजह से सारे झगड़े हैं। इस दृष्टि से देखा जाये तो आप देखेंगे माइनौरिटी किनकी है — भागवानों की माइनौरिटी है और गरीबों की मेजौरिटी है। और यदि किसी के राइट्स एंड इन्टरेस्ट का संरक्षण करना है तो मेजोरिटी का करना है न कि माइनौरिटी का। आज हिन्दुस्तान में जो माइनौरिटी है भागवानों की, उनको तो किसी राइट्स या इन्टरेस्ट के संरक्षण दिये जाने की बात उठती ही नहीं। तो सच्चा सवाल जो है —और इसी सवाल से सारे सवाल पैदा होते हैं। सोशल सवाल में से जो पैदा होते हैं वे दिखावे के हैं—वह यह कि कहां से लाभ कितना मिलता है पंचायत में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, असेम्बली में, पार्लियामेंट में चुन कर जाने के लिये—अपने स्वार्थ के लिये हमें अपनी जाति की याद आती है, अपने मजहब की याद आती है। सच तो यह है कि उसमें मतलब छिपा होता है। अपनी माइनौरिटी जाति का या मजहब का आम जनता को उतना खयाल नहीं है, यदि उन्हें अपनी जाति की, मजहब की याद कोई दिलाते रहते हैं तो वह हमारे जैसे पोलिटिशियन्स, जो अपने अपने स्वार्थ के लिये, अपनी अपनी पोलिटिक्स के लिये इन माइनौरिटीज को बनाये रखते हैं। इसलिये सच्ची माइनौरिटी जो है वह भागवानों की है या पढ़े लिखों की है और वे दोनों 'मेजौरिटी' को एक्स्प्लौइट करते हैं।

[श्री देवकीनन्दन नारायण]

यदि किसी का राइट और इन्टरेस्ट संरक्षित करने की आवश्यकता है तो वह गरीबों को है जो कि पढ़े लिखे बुद्धिमानों और भाग्यवानों द्वारा एक्स्प्लौइट किये जाते हैं और ये सब माइनौरिटी में हैं। ये जितने इलेक्शन के लिये खड़े हुआ करते हैं ये कोई गरीब नहीं हुआ करते, ये पिछड़े हुये नहीं हुआ करते, ये मजहब के बड़े भारी धर्मात्मा नहीं हुआ करते। अपना मतलब सिद्ध करते समय उन्हें याद आता है कि यह हमारे मजहब का है, जाति का है, प्रांत का है, भाषा का है, इसलिये सच्ची माइनौरिटी जो है वह तो आज की माइनौरिटीज को पैदा करने वालों की है। माइनौरिटी कहे जाने वालों को अपना यह कोई ख्याल नहीं है। आप मुसलमानों में जाइये। आमतौर पर जो गरीब मुसलमान हैं उनसे पूछियेगा तो वे कभी आपसे नहीं कहेंगे कि मैं माइनौरिटी का हूं इसलिये मुझे मजदूरी नहीं मिल रही है। आप किसी हिन्दू जाति में जाइये और किसी से पूछिये, वह भी आपसे नहीं कहेगा कि मैं हिन्दू हूं इसलिये मुझे मजदूरी नहीं मिल रही है। तो यह सवाल माइनौरिटी का नहीं है। यह सच्चा सवाल जो है वह निजी स्वार्थ का है, आर्थिक है। और यह आर्थिक सवाल तब तक हल नहीं होगा जब तक हमारे गरीबों के, अनपढ़ों के और पिछड़े हुओं के अन्दर जागृति नहीं आयेगी। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम जो ऊपर वाले हैं सच्ची माइनौरिटी में हैं उनको एक्स्प्लौइट करते रहेंगे। हर एक जाति में हर एक फिरके में, हर एक पंथ में धनवान अपनी तथाकथित माइनौरिटी वाले गरीबों का एक्स्प्लौइटेशन करते हैं और पढ़े लिखे अनपढ़ों का करते हैं। अगर कोई बैरिस्टर है या वकील या डाक्टर है तो वह कहता है मैं आपकी जाति का हूं मैं ही आपका हित कर सकूंगा। और वे बेचारे मान लेते हैं। ये पढ़े लिखे मजहब के ठेकेदार अपने मजहब वालों के पास जाकर कहते हैं, देखिये हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, मुसलमानों की तादाद इतनी है, वगैरह। ऐसे ही लोग माइनौरिटीज को पैदा करते हैं। इसलिये मैं आपसे कहूंगा कि सच्ची माइनौरिटी का तो सवाल है ही नहीं। सच्चा सवाल है मैजौरिटी का, जो गरीब हैं, पिछड़े हुये हैं, अनपढ़ हैं उनके राइट्स एंड इन्टरेस्ट की रक्षा का। और माफ कीजियेगा, मंत्री महोदय, कि आज गरीबों की, अनपढ़ों की और पिछड़े हुओं के हितों की रक्षा जितनी होनी चाहिये थी उतनी नहीं हो रही है। यह मैं आपसे नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं गांवों में चलिये, देहातों में चलिये, स्लम्स में चलिये, आपको दिखायी देगा कि आज गरीब आदमी किस तरह से जिन्दा रह रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल इस देश के सामने जो है वह इस मैजौरिटी का है, न कि माइनौरिटी का। माइनौरिटी कृत्रिम है।

अभी मुझे बड़ा दुख हुआ जब मेरे भाई अनवर साहब यहां तकरीर कर रहे थे। उनकी तकरीर में मुझे कुछ शरारत की झलक दिखाई दी, हालांकि इन्टेन्शन न हो, उनका मकसद न हो, परन्तु उनकी बातों से तो मुझे डर लगा कि ये भाई बातें तो नेशनलिज्म की कर रहे हैं परन्तु दिल में और दिमाग़ में कम्युनलिज्म भरा हुआ है। उन्होंने दो चार बात ऐसी कहीं कि मुसलमानों की डिसएबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि उनमें चारों तरफ़ फ़्रस्ट्रेशन है परन्तु हमें आपके ऊपर भरोसा है। "आपके ऊपर भरोसा है और डिसएबिलिटीज़ बढ़ रही हैं" यह कैसी बात है? एक तरफ़ कहते हैं फ़्रस्ट्रेशन चारों तरफ़ मुसलमानों में बढ़ रहा है और फिर भी "हमारा नेहरू साहब में भरोसा है।" यानी, कितना कांट्रेडिक्शन है? उसके बाद उन्होंने कहा—एक्सटरमिनेशन ऑफ़ मुस्लिम्स—नॉर्थ में ऐसी बहुत सी जमातें हैं जो मुसलमानों को एक्सटरमिनेट, यानी खत्म करना

चाहती हैं। मुझे तो पता नहीं हिन्दुस्तान में कोई ऐसी जमात हो हिन्दुओं में, सिखों में या और जमातों में जो मुसलमानों को यहां से खत्म करना चाहती है। बिलकुल गलत बात है। हां, यह कहियेगा नौकरियों का झगड़ा है, कहीं हिन्दुओं को मिल जाती होंगी, कहीं सिखों को मिल जाती होंगी, कहीं मुसलमानों को मिलती होंगी। यह तो और भी बहुत सी बातों पर निर्भर है। परन्तु यह कहना, हमें एक्सटरमिनेट करना चाहते हैं, इससे बढ़कर गलत बात कोई नहीं हो सकती और मैं हिन्दू महासभावादी नहीं हूं, मैं उसका कट्टर विरोधी हूं, मैं आर० एस० एस० का कट्टर विरोधी हूं परन्तु मैं यह जानता हूं कि हिन्दुस्तान में कोई ऐसी जमात नहीं है जो मुसलमानों को किसी तरह से एक्सटरमिनेट करना चाहती हो। मुसलमान या अन्य धर्मी खुशी से यहां रह कर हिन्दुस्तान को अपना देश मानें, अपनी मातृभूमि मानें, उसके साथ वफादार रहें, अपने को हिन्दुस्तान का नागरिक मानकर, सिटीज़न मानकर औरों के साथ बराबरी के साथ रहें यही हम सब चाहते हैं और यही हमारी अपेक्षा है।

हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में सैकड़ों वर्षों से ये माइनोरिटीज चली आ रही हैं। परन्तु माइनोरिटी का मतलब क्या है यह हमें देखना है। कई कारणों से माइनोरिटीज हमारे यहां बन गई परन्तु आज हमको उन्हें भूलना चाहिये और हम भुला भी रहे हैं। आप देखेंगे कि पहले हमारी जातियां उद्योग और धंधों के नाम पर बनी थीं। आज उन उद्योग और धंधों का जाति के नाम से कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन जाति का नाम रह गया है उद्योग नहीं रहा। इस तरह से जातियां मिटती जा रही हैं। सच्चे मजहब मिट जायें यह मैं नहीं चाहता। मजहब तो रहेंगे और रहने चाहियें। परन्तु मजहब का मतलब यह नहीं है कि पड़ौसी के साथ बैर करो। मजहब का सब से बड़ा यदि कोई उद्देश्य है तो वह यह है कि पड़ोसी के साथ प्रेम करो। जो पड़ौसी के साथ प्रेम नहीं कर सकता वह मजहबी आदमी कहलाने के योग्य नहीं है। इसलिये मुझे कहना है कि हिन्दुस्तान में आज मजहब की लौयलिटी, कास्ट की लौयलिटी, लेंग्वेज लौयलिटी, स्टेट या प्रदेश लौयलिटी ये सब नष्ट होनी चाहियें। एक लौयलिटी रहनी चाहिये, "लौयलिटीटू दी कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया"। चाहे कोई किसी जाति का हो या किसी पंथ का हो या किसी धर्म का हो, वह सबसे पहले भारतीय है और भारतीय के नाते उसकी निष्ठा एक हो।

हमें छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक यह एकनिष्ठा सिखलानी चाहिये और जब तक हम यह नहीं सिखलायेंगे तब तक यह जातीयता का, मजहब का और फिरकावाजी का दोष हिन्दुस्तान से दूर होने वाला नहीं है। क्योंकि हम मजहब को मिटाना नहीं चाहते हैं, जातीयता को अवश्य मिटाना चाहते हैं। जातीयता, जातीयता, कहने से यह मिटने वाली नहीं है। अगर कोई मुझसे यह पूछे कि हिन्दुओं में से जातीयता कब मिटने वाली है तो मैं यह कहूंगा कि जब तक यह कानून नहीं बन जाता है कि अपनी जाति के अन्दर जो शादी करेगा उसको सजा होगी। जब तक इस तरह का कोई लॉ नहीं बनाया जाता तब तक इस देश से जातियां मिटने वाली नहीं हैं। इसका कारण यह है कि हिन्दुस्तान पांच लाख गांवों में फला हुआ है जहां आपका पंहुचना मुश्किल है। और Agricultural Communities are always conservative. सिर्फ भला बुरा कहने से जातियों को मिटा नहीं

[श्री देवकीनन्दन नारायण]

सकते हैं। परन्तु ये जातियां ऐसी नहीं थीं जो पहले किसी कारण से माइनौरिटी बनती हों। तो जैसा मैं ने कहा—loyalty to the Constitution. यह हमारा परम धर्म बने। हमारा कांस्टीट्यूशन ऐसा है कि जिस में सब को स्थान है जो सब मज़हबों को एक निगाह से देखता है, धर्म निरपेक्ष है; धर्म विरोधी नहीं है। वह सारे हिन्दुस्तान को एक राष्ट्र मानता है। वह हिन्दुस्तान के सिटीज़न को एक नागरिक मानता है। इस तरह से हिन्दुस्तान में भाषा की विभिन्नता, मज़हब की विभिन्नता—जातियों की विभिन्नता और बहुत सी विभिन्नतायें चली आ रही हैं।

(*Time bell rings*)

इन सारी विभिन्नताओं को एक सूत्र में बांधने का काम हमारे कांस्टीट्यूशन ने किया है। सब विभिन्नताओं को एकता के सूत्र में बांधने वाली जो शक्ति है, वह हमारा "कांस्टीट्यूशन" है और इस कांस्टीट्यूशन के प्रति हमें अपनी निष्ठा बलवान् बनानी चाहिये। जब तक यह निष्ठा बलवान् नहीं बनेगी, तब तक ऐसे प्रस्ताव, ऐसे पोलिटिशियन्स, ऐसे पढ़े लिखे और ऐसे धनवान् आपको मिलते रहेंगे, जो माइनौरिटीज़ को उभारते रहेंगे, बनाते रहेंगे और अपना स्वार्थ सीधा करते रहेंगे।

यह माइनौरिटी का जो मामला है, वह बहुत ही दुःखदायी और नाजुक मामला है और इसको मिटाने के लिए आपको सारे देश में loyalty to the Constitution. की भावना को फैलाना होगा और मज़हबी लोगों से, फिरकेबाज़ों से और पढ़े लिखे धूर्त पालिटिशियनों से देश की जनता को बचाना होगा।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI B. N. DATAR) Mr. Deputy Chairman, Sir, I have been hearing very intently to the very strong criticisms offered by a number of hon. Members almost unanimously of not only the provisions of this Resolution but also of the object that has been at the back of this particular Resolution. I wish the hon. mover of this Resolution had been present here to hear the trenchant criticism?

Sir, two hon. Members rightly pointed out that this must have been a vote-catching device on the eve of the general elections which are coming soon. That was exactly what my reaction was when this Resolution was first moved last time by the honourable mover, because while dealing with the minorities he confined himself in the course of his fairly long speech only to one community, the name of which it is not necessary for me to mention because it was so clear. In other words, Sir, may I point out, without necessarily being uncharitable to the honourable mover, that this particular community happens to be the present love of the particular party to which the hon. Member belongs. That was why for the first time during the last so many years the sponsor of this Resolution, or a representative of this party, has told us that this particular community has been suffering from a number of disabilities, that they are not properly looked after. It was perfectly open to him, Sir, to have brought in other minorities, other religious minorities or linguistic minorities or as some hon. Member put it, a cultural minority. But all that was not done by him, and that is the reason why I have reason to suspect that this Resolution, especially the object behind this Resolution, is meant for the purpose of making an appeal to a particular community with a view to catching their votes. May I point out that this object is so transparently bad that they cannot deceive any people at all?

Now, coming back to the question of minorities, you will please find why this particular Resolution has been so widely put in that it might include a religious minority as well, a linguistic minority as well, or an economic minority, as some hon. Members rightly pointed out.

Now, Sir, a question arises whether there ought to be any such protection in so far as a particular type of minority is concerned. I shall deal with the question of minorities at some length. But you will please find, Sir, what the hon. mover wants is that there ought to be a permanent Minorities Commission. That is number one. Secondly, it ought to be endowed with statutory powers. Therefore, Sir, an attempt is being made for the first time by my hon. friend, I would almost say that it is a disingenuous attempt, for driving a wedge between a community and a community.

So far as the Constitution is concerned, as my hon. friend, Shri Deokinandan Narayan, rightly pointed out, whenever the question of minorities arises, we have to be extremely careful. The Constitution is a very sacred document which has embodied all the different aspects of the common question of India's nationality. India is one in spite of different types of languages and religions. But in the midst of all these diversities we have to develop a common nationality. Therefore, whenever we consider the question of the development of the nation and the interest of the nation, you cannot afford to think in terms especially either of religion or of language.

It is true, Sir, that there are different religions. It is also true that there are different languages. Therefore, a question arose and the framers of the Constitution had to devise a Constitution in the midst of the unity of India with certain diversities here and there. For that purpose, what they did was, they devised a common nationality—that should be clearly understood—for the whole of India and in so far as religious minorities were concerned, they were given certain rights. I would not go into the details regarding the provisions of the Fundamental Rights regarding the practice of religion. They are articles 28, 29 and 30. Certain rights have been given to the religious minorities and beyond that it would not be proper to bring in the religious minorities for—let it be understood—political rights. For that we have to be extremely careful. I would also point out that while we have to develop a common nationality, the members of the Indian nation whether they are Hindus, Muslims, Christians or others, all of us, have to understand that we are members of one nation, whatever might be the apparently dividing line, namely, our religion or our language. Therefore certain rights in respect of religious minorities were given. They were Fundamental Rights and most of them are justiciable rights. Here we stopped so far as the religious rights were concerned. Then a question arose, what ought to be the attitude of not only the Government but the society regarding the languages. It was true that there were certain interests of the regional languages. Now these languages required to be developed but they were not meant for dividing one man from the other. So in 1956 when the States were formed, to a certain extent, on the basis of language, what was done was not to have a State with cent. per. cent. people belonging to the regional languages because there were bound to be people belonging to different languages. That was the reason why this question was considered at great length and the S.R.C. also went into this question of linguistic minorities. It was bound to arise here and there because they were likely to feel that their rights and safeguards given to them might or might not be properly implemented. So this question was considered first by the S.R.C. and they dealt with the question whether we should have a permanent Minorities Commission. They went into it very carefully and

[Shri B. N. Datar]

shrewdly. They found out that it would not be proper to set up a permanent Minorities Commission because the result, if not the actual effect, would be that a permanent wedge would be driven between one community and another community. So far as language minorities were concerned, they had a right so far as their own languages were concerned. They had also an obligation to understand the language of the majority in the particular State. It is only by thus coming together that the members of the two language groups would come together and would harmoniously develop but it was found at the time when the S.R.C. had to consider this that some machinery should be devised for safeguarding the rights of linguistic minorities only—please understand it very correctly—not all types of minorities. There was a long discussion in Parliament—in this House and the other—and after full consideration what was conceded was that only in respect of linguistic minorities certain rights should be extended and certain rights should be safeguarded and an officer should be appointed by the President for making a report on the question whether these rights of the linguistic minorities are or are not properly safeguarded. Therefore please understand that this larger question, a very wide question, that the mover has brought up before the House was considered in all its aspects and it was believed—and in my opinion rightly believed—that the setting up of a permanent Minorities Commission statutorily or otherwise would be, as some Members have rightly pointed out, a source of danger to the nation and to the communities of the nation. That is the reason why that was rightly rejected. Therefore there cannot be any question of a Minorities Commission as such.

In respect of other categories of minorities, it is not necessary for me to deal with them here except to point out that so far as the economic minorities are concerned, that is a question which the country itself, the Government themselves, have to consider because there are no economic minorities. There are economically bad majorities. So, so far as the economic side is concerned, that is common to the whole of India. One has to be very careful in having any such commission. Against the background of what I have said, we should also take into account how there are disruptive tendencies here and there, either on the ground of religion or language. We have seen how religion is misunderstood as the only force that binds certain persons together and that language is one which ought to bind certain persons together at the cost of others. That is what we have to understand very clearly. Therefore, either so far as religion is concerned or so far as language is concerned, we have to be extremely careful not to allow them to enter or tresspass upon the field where they have no legitimate application at all. Therefore we should be careful in seeing about that; if we are a majority community or if we are a minority community, we have to be extremely careful as Gandhiji pointed out. Gandhiji had told us that so far as the majority community is concerned, it has to be extremely generous towards the minorities. So far as the minorities are concerned, it is their duty not always to remain or always nurse what may be called a separatist feeling. I would invite the attention of the House to what Mr. Bhupesh Gupta told us. He began to deal with the so-called disabilities of the Muslim community and did you remember that at the last time when he dealt with this particular question, he told us that within the last 8 to 10 years not a single Muslim had been appointed to the Bench at the Calcutta High Court? Now it is perfectly possible to misinterpret what is done or what is not done. But the question is whether you can look at it from this particular point of view. One has to be extremely careful. The Constitution as well as the Government and the people are trying their

best to rise above, what you can call, the communal approach to all such questions. If, for example, you have to find out how many people belong to a particular community or how many belong to a particular religion, then there will be no end to that. Let us understand it very clearly. Therefore I would like to appeal to the whole House to understand what we are at present doing. In the background of what happened at the various places, I need not mention about the religious fanaticisms here and there, they often intrude upon provinces where they ought not to go. This linguistic tyranny also comes in where it ought not to come at all. After all, we belong to one nation, and whatever might be my language, the language cannot divide me from my friend but unfortunately it has so happened. That is the reason why during the last some months we are actively at the point of developing correct, sound and healthy national integration. The Constitution itself is the greatest and to a large extent, a very effective attempt at national integration and Shri Deokinandan Narayan was perfectly right in pointing out that our highest loyalty and our exclusive loyalty ought to be to the Constitution. That naturally pre-supposes national integration. Under these circumstances we in India must develop that sense of complete union, not only a sense of geographical union, but also what may be called emotional integration. Geographical union is there. We have also the President and we are all under the President's rule But let us also try to develop what is called the emotional integration in the sense that we do not create walls between man and man, between India and India. In the south, an attempt is being made to introduce certain forces of disruption and here also we find some other forces working in other ways, trying to set up a wall between man and man. All this has got to disappear and the sooner they disappear the better for the country. For this purpose we had the conference of the Chief Ministers and thereafter attempts are being made to carry on the work of national reconstruction in all these things. After all, this is the greatest national reconstruction, namely national consolidation. For this purpose action is being taken at the zonal levels, at the district levels and at other levels also. The Chief Ministers and all the other officers in the different Ministries in the various States are trying to see that while doing everything that is possible to satisfy the legitimate demands of the linguistic and other minorities, we also see that every man, woman and child is properly imbued with the idea and belief that he is an Indian first and an Indian last. For this purpose the recent Integration conference took certain steps for educating the young minds of our children. Oftentimes, what happens is, if these religious or linguistic tendencies are built up, then just because I belong to a particular religion or to a particular linguistic group, one who does not belong to it, I feel, is not my brother or my sister. We have certain forces which are highly disruptive. All these have to disappear and for this every child has to be properly brought up and developed with this idea of complete unity, with this sense of complete harmony with the different people that inhabit India. It is immaterial whether one professes Christianity, or the Muslim religion or the Hindu religion, or whether one is an untouchable, as they are sometimes called, or any other person, there should be this sense of unity and harmony. After all, the common cementing force is nationalism and national unity. Let us take up this great task. We have, as the House is aware, the National Integration Council which has also been functioning. The greatest attention has to be paid to the question of developing this national integration.

The short question that arises at this stage is whether, with this background, the present Resolution which

[Shri B. N. Datar]

says that the Government should set up a permanent Minorities Commission, is desirable or not. It says:

> "This House is of opinion that Government should set up a permanent Minorities Commission,"—

Please mark the word "permanent"—

> "vested with necessary statutory powers, for protecting and safeguarding the rights and interests of the minorities in the country."

As I have pointed out, this Resolution suffers from too much of width, in the sense that it has brought in all the minorities. The question that arises here is whether the members of the minority communities have to look only to this Commission for safeguarding their rights and interests or whether they are to look to society. Certainly they have to look to society at large and also to the Government and the officers and to the Commissioner for Linguistic Minorities, to get their legitimate rights duly satisfied and their legitimate problems duly solved. For this particular objective we have all been striving so hard in spite of so many attempts at disunion and in spite of so many disintegrating factors. We are trying to develop that sense of emotional integration. The question arises whether this Resolution adopted at this time by an Act of Parliament, is necessary. Mr. Gupta wants that there ought to be an Act of Parliament, because he is anxious that this commission should have statutory powers. Well, it is left only to him to define what a particular minority is. As has been so eloquently pointed out by Shri Deokinandan Narayan, and several other hon. Members, there can hardly be any person in India who cannot claim that he is a member of a minority community. Therefore, it would be entirely wrong to adopt such a Resolution if we take into consideration the circumstances that obtain, quite apart from the motive that has actuated the hon. mover of the Resolution. I should like to point out that—and it has been rightly pointed out by others also—that this Resolution has a highly mischievous content and it is likely to undo whatever we have been doing against odds during the last so many years in the direction of building up that concept of unity and national integration. Therefore, I would request the House to rightly throw out this Resolution. I say this for two purposes. First of all, the hon. Member has brought this forward only to make an appeal—and a disingenuous appeal it is—to only one community. He does not think of any others. He is bringing in certain exploded theories in support of his claim for a particular community. I am quite sure that hon. Members of that community—and a number of such friends have spoken from that community—were quite right in asking themselves to be saved from such a friend.

AN. HON. MEMBER: The so-called friend.

SHRI B. N. DATAR: Therefore, I appeal to all hon. Members of the House to throw out this highly mischievous Resolution.

SHRI M. GOVINDA REDDY (Mysore): Mr. Deputy Chairman, I submit that this Resolution would not admit of any analysis even for a moment. That being the case, I do not understand how my hon. friend Shri Bhupesh Gupta who usually adopts a very critical approach to everything, should have brought up such a Resolution which does not admit of any scrutiny at all. As has been pointed out, his object in bringing this Resolution seems to be to stage an election stunt rather than to further the interests of the minorities themselves.

This Resolution involves, first of all, the question of minorities. As the hon. Minister has just now said and as Shri Deokinandan Narayan has also pointed out, there is this question: What is a minority? The

term "minority" has not been defined in the Constitution. To arrive at a definition of the term "minority community", shall we look at the people from the point of view of their bulk in the country as a whole and say that these sections of the people form a minority community? Or shall we look at the economic position of a particular section in relation to the economic position of the mass of the people and say that this section is a minority community? Or shall we look at them from their educational progress and say that such and such a section has made only this much progress compared to the other sections and so this is a minority community? Or do we take religion as the basis for determining whether a particular section of society is a minority community or not? What is it to be? There are so many respects in which we can say that a particular section of our people are backward or are handicapped or need encouragement. Here, the hon. Member does not suggest anything. Therefore, as the hon. Minister said just now, it is very wide, the Resolution is much too wide to be accepted by the House.

Now, what are these interests of the minorities that we have to consider? If we could arrive at a definite connotation of the term "minority", then we could say what are these interests of the minorities that are to be protected and that are to be safeguarded. Shall we say that their educational interests should be considered? Or will it be their religious interests or their interest in the matter of employment in the services and so on? This also is a thing which cannot be definitely conjectured and, therefore, it does not admit of any particular solution.

Now, this Resolution thinks of appointing a permanent Minorities Commission and he is not satisfied with the demand for the appointment of a Minorities Commission; he wants it to be invested with statutory powers, statutory powers to protect the interests of the so-called minorities and statutory powers to safeguard their interests. Now, if we project this to its logical conclusion it simply means this that he wants another Government, a super-Government, to be in charge of these affairs. Let us for a moment think that there is a Commission which is appointed. Well, it will have statutory powers of implementation. It is not just a question of a Commission which would submit its Report. He wants this to be a Commission having adequate statutory powers of implementation in the matter of protection and safeguarding of the interests of the minorities. Supposing we appoint such a Commission and it has these statutory powers; how awkward would it be for any Government to have such a super-body over them because it will be open to that Commission to find fault with any Government and say, 'You have not done this for the minorities or you have not done that for the minorities.' It may be in clash with the interests of the other sections of the people and no Government will tolerate such a super-body questioning its actions in this manner. This will be a super-body with administrative powers, with powers to implement certain projects and policies. This is a thing which is inconceivable, which is impracticable, which is inadvisable.

I took out the Constitution for this purpose and was going through the provisions. The hon. Minister, I am glad to say, has referred to the provisions. Although the hon. Member has used the general term 'minorities' all along, as the hon. Minister was saying, the reference was only to one particular community on the basis of religion. If we take that as the basis, if we take any particular community which follows a particular religion, then we have ample safeguards provided in the Constitution. The framers of the Constitution were eminent men in the country, men who had won the adoration and admiration of the entire people of the country and therefore they were able to

[Shri M. Govinda Reddy]

visualise the problems that may arise in the sphere of social affairs and in the sphere of political affairs and they have made adequate provisions. If you take, for instance, any particular sect on the basis of religion as a minority, then that sect or caste or creed now has got the right under the Constitution to follow its own religion, to pursue its own method of worship. It is provided in the Constitution that any particular religious group or sect can have their own educational institutions even and it is also provided that the State shall not discriminate against any person or any group of people on the ground of sex or religion or such things. So there are ample provisions and safeguards for protecting the interests of the minorities. In the field of education they are free to have their own educational institutions and in fact although it affects the integration of the country to a certain extent we are now suffering some denominational educational institutions in the country. There are Muslim educational institutions; there may be other educational institutions run by religious mutts and the State does not interfere in the matter of running these institutions. On the other hand, the State extends to them as much help as it can give to any other educational institution. If we take services, there nobody is prevented because of the fact that he belongs to a particular area or a particular community from entering Service. In the field of administration there is to be no discrimination observed against any person on the ground of religion or sex. Even supposing we take, as he has attempted to do, religion as the basis for determining minority, what is the handicap that any particular sect or a particular group in the country is suffering from? Sir, we have had some Conventions like the Hindu Convention, the Muslim Convention and the like. I have followed the proceedings of these Conventions and also or religious bodies and caste organisations which have expressed dissatisfaction in this manner. If you go through the proceedings of these bodies' meetings, you will find that they have not been able to point in their conferences or conventions that any injustice has been done to any one of them. In a general way they may say that they are not represented in the Services. In a general way they may say such things as the hon. Member said that a Muslim Judge has not been appointed in one of the courts. But as the hon. Minister has said, the very point of view that a particular caste man should be appointed as Judge is wrong. There has not been any instance anywhere that discrimination is made against anybody. Granting that discrimination is made, it is open to any individual to go to a court of law and I think the Supreme Court is empowered by the Constitution to go into the question of deciding whether any discrimination has been made against any individual or against any particular group of people in the country. So the Constitution has taken pretty good care to see that the various groups comprising India should advance and make progress. Therefore there can be no reason for any particular section in the country to say that they are discriminated against in any manner whatsoever. As I said, this is only an election stunt. It is very inopportune that the hon. Member has brought this forward particularly in view of the vigorous attempts that the Government have been making to promote national integration. I am not going into the question of national integration, but here it is desirable to point out that attempts of this nature should be discouraged. And in order to discourage attempts of this nature we ought to remove whatever distinction there is now in the nature of promoting sectional interests.

I would advise the Government to observe a particular code, a particular principle, in aiding these denominational institutions. Wherever the Government extends financial help to any

minority institution or to any denominational institution which is run by any religious body, then I would like a safeguard to be introduced by making a condition before the assistance is given that that institution which seeks Government aid, which seeks Government patronage, must be open to everyone, to people of all religions, to people of all castes, to people of all creeds. This is one way in which we can remove this sectarian outlook. The other way is to see that in Services there is not that attraction for people to rush into Services on the basis of caste, creed, etc. Now, Sir, there is a wide difference between people who are not in Service and people who are in Service. In the matter of standard of living it makes a lot of difference. Particularly certain concessions are extended to people in Services. I do not grudge them these concessions. I am only pointing out that Services now carry with them a good deal of attraction, attraction of regular salaries, salaries which are far removed from the average per capita income, salaries which assure a steady life, a high standard of living and favourable opportunities for education, recreaction, etc These attractions are responsible for people rushing into Services on the ground that they are Muslims or Sikhs or Jains or people belonging to Scheduled Castes. If this attraction is removed, if there is no temptation for people to rush in for Services then much of this disintegration will vanish. So it is important that we should take care to see that Services do not have such attraction which makes people to rush in for them on the ground of caste, creed or religion. The other thing I wish to refer to is this. I wish the other Resolution had come up. We should have a Civil Code. Now, people have begun to think on narrow lines and sectional lines and we have to build up a national outlook. If the Government had observed article 44 of the Constitution and promoted adequate steps, it would have been better. I think, therefore, that this House should throw out this Resolution.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned *sine die*.

The House then adjourned *sine die* at five of the clock.

GMGIPND—RS—674 RS—[J. C. No. 12381/61-62—P.W.—D/S—2-3-62—500